● वर्ष-3
● अंक-56
रायपुर, शुक्रवार
13 अक्टूबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कान के पर्दे खराब करेगा ईयरफोन

# इजरायल ने सीरिया पर किया हमला

## हमास से जंग के बीच दो मुख्य हवाई अड्डों को बनाया निशाना

**नईदिल्ली।** इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि आतंकवादी समूह के हिंसक सप्ताहांत हमले के जवाब में इजरायल हमास को कुचलने और नष्ट करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। हमास और लेबनान के बाद अब सीरिया की तरफ से भी गोलीबारी की खबर सामने आई है। इस्राइली सेना ने कहा कि वह सीरिया की ओर से की गई गोलाबारी के जवाब में तोपों से गोले दागने के साथ ही मोर्टार भी दाग रही। गोलाबारी ऐसे समय में सामने आई। है जब इस्राइल हमास के हमले के जवाब में गाजा में हमले कर रहा है। अब इजरायल की तरफ से सीरिया पर हमले किए गए हैं। इजरायल ने सीरिया के दो एयरपोर्ट पर हवाई हमले किए है।

सीरियाई रिपोर्टों में गुरुवार को आरोप लगाया गया कि इज़राइल ने सीरिया में दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले किए। सीरियाई राज्य मीडिया का कहना है कि इज़रायली हमलों के

बाद दमिश्क, अलेप्पो हवाई अड्डे सेवा से बाहर हैं। सीरियाई रिपोर्टों के अनुसार, सीरियाई हवाई सुरक्षा ने हमले का जवाब दिया। इस सप्ताह की शुरुआत में सीरिया से इज़राइल पर गोले दागे गए। कथित इजरायली हवाई हमले आईडीएफ के हमास के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन स्वोर्ड्स ऑफ आयरन के बीच हुए हैं और मंगलवार रात को सीरियाई सीमा से इजरायल में गोले दागे गए थे। सेना ने कहा कि कुछ गोले संभवत: इजराइल के गोलान हाइट्स में खुले मैदान में गिरे। आईडीएफ ने सीरियाई गोलाबारी के स्रोत की ओर तोपखाने और मोर्टार फायर से जवाब दिया।

230 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान इजरायल से होगी रवाना, विदेश मंत्रालय ने कहा- हमारे पास सभी विकल्प हैं

इजराइल में फंसे भारतीयों को लेकर पहली चार्टर उड़ान 12 अक्टूबर यानी आज रात बेन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना होगी। यह उड़ान इज़राइल में रहने वाले लगभग 230 भारतीयों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले जाएगी। फ्लाइट इजराइल से रात 9 बजे रवाना होगी और इसमें सवार यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। उनकी वापसी का खर्च सरकार उठा रही है। एयर इंडिया ने 7 अक्टूबर को इज़राइल से अपनी उड़ान तुरंत निलंबित कर दी थी। ऐसे में जो लोग भारत की यात्रा पर आने वाले थे उन्हें भी पहली उड़ान में शामिल किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जैसा कि कल विदेश मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, इजराइल से वापस आने को इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। पहली चार्टर उड़ान भारतीय नागरिकों को लेने के लिए आज रात तेल अवीव पहुंचेगी। चार्टर उड़ान आज देर शाम तेल अवीव पहुंचेगी। इसमें 230 यात्रियों के सवार होने की उम्मीद है। हमारे पास सभी विकल्प हैं, लेकिन निकासी में भारतीय वायुसेना की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल में हमास आतंकियों के साथ चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा बुधवार को घोषित ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इससे पहले आज, उन्होंने इज़राइल से प्रस्थान करने वाली पहली चार्टर उड़ान की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले, उन्होंने स्थिति की निगरानी करने और उन भारतीयों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली में एक चौबीसों घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष और तेल अवीव और रामल्ला में अलग आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित की, जिन्हें मदद की आवश्यकता हो सकती है।

एक ट्वीट में इज़राइल में भारतीय दूतावास ने कहा कि उसने गुरुवार को विशेष उड़ान के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप ईमेल की। इसमें कहा गया है कि अन्य पंजीकृत लोगों को संदेश अगली उड़ानों के लिए भेजा जाएगा। मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने पीटीआई को बताया कि देश में 20,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जो वर्तमान में फिलिस्तीनी समूह हमास के साथ युद्ध में है।

### भारत के स्थायी मिशन के परिसर में लगी पट्टिका

# संयुक्त राष्ट्र में वसुधैव कुटुंबकम

**नईदिल्ली।** अगस्त का महीना था जब भारत जी20 के सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में लगा था। ठीक उसी वक्त चीन भारत के खिलाफ साजिशें रचने में लगा था। चीन वसुधैव कुटुंबकम (दुनिया एक परिवार है) को भारत की जी 20 अध्यक्षता की थीम के रूप में शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। अब उसी भारत के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है। भारत वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को आत्मसात करता चलता है। इसका अर्थ है कि हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं।

### स्थायी मिशन के परिसर में पट्टिका स्थापित

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के परिसर में वसुधैव कुटुंबकम शिलालेख वाली एक पट्टिका स्थापित की गई है, जो एकता और वैश्विक सहयोग के लिए नई दिल्ली की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पट्टिका का अनावरण एक विशेष समारोह में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने किया।

हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम और अंग्रेजी में द वर्ल्ड इज वन फैमिली वाक्यांश के साथ सोने की रंग की पट्टिका शहर में भारत के स्थायी मिशन के परिसर के प्रवेश द्वार के अंदर एक दीवार पर सजी हुई है। पट्टिका का अनावरण आईसीसीआर के साथ भारत के स्थायी मिशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वसुधैव कुटुंबकम पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के एक दिन बाद हुआ। वर्ष 2023 के लिए भारत की जी 20 प्रेसीडेंसी ने वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी - एक परिवार - एक भविष्य विषय को अपनाया, जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एकता और सहयोग को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चीन ने जताई थी आपत्ति

चीन ने पिछले महीने की जी 20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ-साथ कई अन्य समान जी 20 दस्तावेजों के दौरान आउटकम डॉक्यूमेंट में इस वाक्यांश और इसके उपयोग का विरोध किया था, मुख्य रूप से क्योंकि संस्कृत संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त छह आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं थी। इसी तरह से जी 20 के बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी इस शब्द का उपयोग है। चीन ने तर्क दिया कि जी-20 दस्तावेज आधिकारिक तौर पर वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। उसका कहना है कि यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इस भाषा को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की तरफ से मान्यता दी गई। छह आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है।

### यही भारत की पहचान

सहस्त्रबुद्धे ने अनावरण के अवसर पर कहा कि एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम के पीछे के दर्शन ने आधुनिक भाषा में जिसे हम ब्रांड इंडिया कह सकते हैं, बनाया है।

# सनातन से ही चल रहा संसार: मोहन भागवत

■ इसे नष्ट करने की बात करना कुल्हाड़ी पर पैर रखने के समान

**नईदिल्ली।** देश में चल रहे सनातन धर्म विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से ही संसार चल रहा है और चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसे नष्ट करने की बात करना कुल्हाड़ी पर पैर रखने के समान है। भागवत ने कहा कि मुझे ऐसे लोगों पर दया आती है जो ऐसा कहते हैं, मैं उन पर क्रोधित नहीं हूं। ऐसे बयान ज्ञान की कमी के कारण हैं। सनातन की रक्षा कैसे करें ये संतों ने पहले ही बता दिया है। रोहतक स्थित श्री बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में शंखढाल व मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने मोहन भागवत पहुंचे थे।

मोहन भागवत के अलावा इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के ष्टरू योगी आदित्यनाथ और योगगुरू स्वामी रामदेव भी शामिल हुए। आपको बता दें कि देश में सनातन धर्म को लेकर उस समय विवाद शुरू हो गया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। इसके बाद हंगामा हो गया है। उदयनिधि ने कहा कि इसका सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए। इसका सफाया होना चाहिए। उन्होंने %सनातन धर्म% की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू बुखार से भी की और कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए।

इससे पहले मोहन भागवत ने कहा कि भारत की पांच हजार साल पुरानी संस्कृति धर्मनिरपेक्ष है और उन्होंने लोगों से एकजुट रहकर दुनिया के सामने मानव व्यवहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करने का आह्वान किया। भागवत ने लोगों से अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति, प्रेम और समर्पण का भाव रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हम अपनी मातृभूमि को हमारी राष्ट्रीय एकता का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। कुछ वर्ष पहले घर वापसी विवाद के दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी मुलाकात का संदर्भ देते हुए भागवत ने कहा, उन्होंने (प्रणब ने) कहा था कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। वह कुछ देर के लिए चुप रहे और उसके बाद कहा कि हम हमारे संविधान की वजह से ही धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं बल्कि संविधान की रचना करने वाले महान नेताओं के कारण भी धर्मनिरपेक्ष हैं क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष थे। भागवत ने पूर्व राष्ट्रपति की बातों को याद करते हुए कहा, वह फिर क्षण भर के लिए रुके और उसके बाद कहा कि हम तभी से धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं।

गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि उत्सव से पहले एक युवक को सिर पर 3 किलो की पगड़ी पहने देखा गया जो दिखने में बेहद अद्भुत है।गुजरात में हर साल मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है नौ दिवसीय नवरात्रि का त्योहार।इस बीच गांधीनगर में नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस त्योहार को लेकर जो रौनक और उल?लास गुजरात में नजर आता है वो और कहीं नहीं दिखता। लोग घर से बाहर निकलते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं और यह देश भर से पर्यटकों को भी उत्सव का अनुभव लेने के लिए आकर्षित करता है।जहां नौ दिन तक चलने वाले गरबा महोत्सव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं वहीं इसे लेकर बाजारों में रौनक दिख रही है।

**प्रमुख समाचार**

## बांग्लादेशियों को भारत में बसा रहे थे, विदेश से फंडिंग भी हुई

**सहारनपुर।** देवबंद और वाराणसी एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) की टीम ने बुधवार को देवबंद से पकड़े गए बांग्लादेशी युवकों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तीनों के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज कराया गया है। जिसके बाद एटीएस की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें बताया कि आरोपी मानव तस्करी कर बांग्लादेशियों को भारत में लाकर बसाते थे और इनके फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराते थे। इन्हें विदेश से 20 करोड़ की फडिंग भी हुई है। इनके देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के भी सुबूत मिले हैं। एटीएस के अनुसार, उन्हें सूचना मिली कि प्रदेश में कुछ बांग्लादेशी मानव तस्करी कर रहे हैं, जो बांग्लादेशियों को भारत में लाकर बसाने और उनके फर्जी दस्तावेज भी तैयार करा रहे हैं। वाराणसी और देवबंद एटीएस ने बुधवार को आदिल मोहम्मद असरफी निवासी मीरपुर बांग्लादेश को वाराणसी से गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से बांग्लादेश का निवासी है, लेकिन वह देवबंद की मदीना कॉलोनी में रह रहे नजीबुल शेख निवासी हलदर पाड़ा गुरानबोस भरतगढ़ थाना बासंती जनपद दक्षिण 24 पश्चिम बंगाल और अबू हुरायरा गाजी निवासी कालूतला रामेश्वरपुर थाना हसनाबाद पश्चिम बंगाल की मदद से भारत आया है।

## सितंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 5.02 फीसदी

**नईदिल्ली।** गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर तीन महीने के निचले स्तर 5.02 पर आ गई। मुद्रास्फीति दो महीने के अंतराल के बाद रिज़र्व बैंक

के 6 प्रतिशत से नीचे के आरामदायक स्तर पर वापस आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 6.83 प्रतिशत और सितंबर 2022 में 7.41 प्रतिशत थी। पिछला निचला स्तर इस साल जून में था जब रीडिंग 4.87 प्रतिशत थी। खुदरा मुद्रास्फीति दो महीने के अंतराल के बाद फिर से रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में आ गई है। रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने का दायित्व मिला हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में खाद्य उत्पादों की कीमतें घटने से खाद्य मुद्रास्फीति 6.56 प्रतिशत पर आ गई जबकि अगस्त में यह 9.94 प्रतिशत रही थी। आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है।

## चुनावों में मुफ्त की सौगातों को कोर्ट भी खत्म नहीं करा सका

**नईदिल्ली।** पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त सुविधाएं देने की भाजपा और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा के बीच, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि चुनावी रियायतें देना कानूनी रूप से एक वैध

गतिविधि है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे खत्म नहीं कर सकता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, मुफ्त का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, जो इसे अवैध घोषित कर सकता था। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। अदालत इसे भ्रष्ट आचरण कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कानूनी तौर पर, मुफ़्त चीज़ें और गारंटी देना एक वैध राजनीतिक गतिविधि है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे ख़त्म नहीं कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की घोषणा लोकलुभावनवाद के तड़के के साथ की जाती है। पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने चुनाव वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान से उस याचिका पर जवाब मांगा था।

## उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

**नईदिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समय की कमी का हवाला देते हुए दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू विद्वान और कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। वह सितंबर 2020 से तीन

साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले साल उसे जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह एक युवा छात्र है, पीएचडी धारक है, तीन साल से सलाखों के पीछे है, यह चल रहा है। सिब्बल ने कहा कि अभी आरोप तय होने की कोई संभावना नहीं है।

## कनाडा ने भारत में होने वाले पी20 समिट का किया बहिष्कार

**नईदिल्ली।** भारत द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पी 20 कार्यक्रम से पहले कनाडा के सीनेट के स्पीकर समूह 20 के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव उच्च बना हुआ है। खबर सामने आई है कि कनाडा की सीनेट के अध्यक्ष रेमोंडे गैगने

इस शुक्रवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) में शामिल नहीं होंगे। कनाडा के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आगामी पी 20 कार्यक्रम के लिए उनकी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया, और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को पी 20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) का उद्घाटन करेंगे। पहले खबर आई थी कि पी20 शिखर सम्मेलन में कनाडा का प्रतिनिधित्व सीनेट के अध्यक्ष रेमोंडे गैग्ने करेंगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा जून में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों को शामिल करने के बाद कनाडा के साथ भारत के संबंध गंभीर तनाव में आ गए हैं। तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में 350 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

**आरक्षण:**

# समानता जो विकास के साथ चले, व्यवस्था की विषमताओं को दूर करने की जरूरत

**शंकर अय्यर**

जाति आधारित जनगणना से संबंधित सवाल पिछले करीब दो दशकों से संसद में नियमित तौर पर उठते रहे हैं। पर, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से अब तक जो भी जनगणनाएं कराई हैं, उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के अलावा जाति आधारित जनगणना नहीं कराई है। इसी वजह से कई बार हमें चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार ने हाल ही में जातियों पर सर्वे के नतीजे घोषित कर चुनौती पेश कर दी है।

सर्वे के मुताबिक, पिछड़ा वर्ग की आबादी आरक्षण के वर्तमान मॉडल में जितनी मानी जाती है, उससे कहीं ज्यादा है। सर्वे कहता है अन्य पिछड़ा वर्ग कुल आबादी का 27 फीसदी और अति पिछड़ा वर्ग कुल आबादी का 36 फीसदी है। स्वाभाविक है कि बिहार में जाति आधारित गणना ने भारतीय राजनीति में एक तूफान ला दिया है। इससे देश के समाज व राजनीति में जातियों और कोटा की व्यवस्था में निहित खामियों पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

आश्चर्य नहीं कि विपक्ष ने एक सुर में एक राष्ट्रीय जाति आधारित गणना की मांग करनी शुरू कर दी है। पर इससे जुड़े 'अगर', 'कैसे' और 'कब' जैसे सवाल राजनीति की दिशा व राजनीतिक दलों के रुख पर निर्भर करेंगे। इस पर बयानबाजी तेज हो चुकी है और इसकी गूंज आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सुनाई देनी तय है। यह देखना भी रोचक है कि आजादी के सात दशक और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के तीन दशक बाद भी जाति का मुद्दा राजनीति में हलचल पैदा करने की ताकत रखे हुए है। सर्वे में जो आंकड़े सामने आते हैं, वे इस स्थिति के कारणों व नतीजों को उजागर करते हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना पर विचार करें, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान 18.3 फीसदी है और यह 45 फीसदी से ज्यादा कार्यबल को रोजगार देता है। जाहिर है, तकरीबन आधा कार्यबल राष्ट्रीय आय के छठे हिस्से पर निर्भर करता है। परिचालन जोत का औसत आकार बमुश्किल 1.08 हेक्टेयर है और इससे स्वाभाविक ही उपज और आय में कमी आती है। एक अगस्त को, सरकार ने संसद को सूचित किया कि पूरे भारत में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी, जिसमें? झारखंड में 4,895

रुपये, बिहार में 7,542 रुपये और उत्तर प्रदेश में 8,061 रुपये थी।

पर, कोटा में उचित हिस्सेदारी की मांग केवल पिछड़े वर्गों तक ही सीमित नहीं है। मराठा, पाटीदार, जाट और कापू जैसे अपेक्षाकृत शक्तिशाली वर्गों? की तरफ से भी हाल के दिनों में आरक्षण के लिए आंदोलन किए गए हैं। इसके पीछे की वजह कृषि की घटती व्यवहार्यता है। औद्योगिक और कृषि प्रधान राज्यों के बीच जो फर्क होता है, वह राष्ट्रीय आंकड़ों में भी परिलक्षित होता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,96,983 रुपये है। इस सूची में सबसे ऊपर तेलंगाना है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 3,08,732 रुपये है।? इसके बाद करीब तीन लाख रुपये की प्रति व्यक्ति आय के साथ कर्नाटक और 2.96 लाख रुपये के साथ हरियाणा है। इसके बिल्कुल उलट, बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी राष्ट्रीय औसत का लगभग एक-चौथाई यानी 54,383 रुपये है, उत्तर प्रदेश में यह 79,396 रुपये और झारखंड में 80,060 रुपये है।

कम आय और इससे पैदा होने वाली असमानता का असर संपत्ति पर स्वामित्व के रूप में प्रकट होता है। ऋण और निवेश पर 77वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट से पता चलता है कि शीर्ष 10 फीसदी परिवारों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति है, जबकि नीचे के 50 फीसदी के पास 10 फीसदी से भी कम संपत्ति है। जरूरतों का परिदृश्य कल्याणकारी गतिविधियों के विस्तार से स्पष्ट होता है। रोजगार की उम्मीद और वास्तविकता के बीच अंतर को पाटने के लिए 2005 में ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा बनाई गई थी। 2023 में इसमें 26.59 करोड़ से अधिक पंजीकृत कर्मचारी हैं।

पिछले तीन वर्षों में, मनरेगा पर औसत खर्च तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये, जबकि शुरुआत से अब तक कुल खर्च 9.68 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दस वर्ष पुराना है। इस साल सरकार ने 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए करीब दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

# भरतपुर में कायाकल्प को तरस रहा है प्राथमिक स्कूल, किराए के भवन में हो रही बच्चों की पढ़ाई

**मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर।** छत्तीसगढ़ में सरकार ने आत्मानंद स्कूलों के जरिए शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठाया। जिसके तहत कई जिलों के अंदर आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की गई। इन स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ हिंदी में भी शिक्षकों की व्यवस्था की गई। बच्चों को 12वीं तक नि:शुल्क उच्च स्तर की शिक्षा इन स्कूलों के जरिए दी जाती है। बावजूद इसके प्रदेश के कुछ जिलों में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। ताजा मामला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का है। जहां के भरतपुर सोनहत मुख्तियार पारा सरकारी स्कूल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है।

### प्राथमिक स्कूल का बुरा हाल

चुनाव से पहले सरकार और जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात कह रही है। लेकिन भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के मुख्तियार पारा गांव की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है।इस गांव में ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शाला का संचालन होता है।लेकिन इसे बच्चों की बदनसीबी ही कहेंगे कि ये स्कूल एक निजी भवन में संचालित है। जहां बच्चों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

### खतरनाक स्कूल में कैसे हो पढ़ाई?

मुख्तियार पारा में संचालित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक का क्लास संचालित है। जिसमें लगभग पैंतालीस छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं।लेकिन स्कूल की हालत काफी खराब है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने बताया कि स्कूल की दीवारें और छत जर्जर हो चुके हैं।जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए बच्चे किराए के स्कूल के बरामदे में पढ़ाई करते हैं।

### जनप्रतिनिधियों की उदासीनता आई सामने

मुख्तियार पारा की उप सरपंच मालती सिंह के मुताबिक चार साल से प्राथमिक शाला का भवन जर्जर और दयनीय स्थिति में है।जिसकी वजह से एक व्यक्ति के निजी भवन में स्कूल का संचालन किया जा रहा है।इसे लेकर जिले के अधिकारी से लेकर स्थानीय विधायक गुलाब कमरो को जानकारी दी गई।लेकिन प्राथमिक शाला के लिए नए भवन का निर्माण नहीं कराया जा सका है। लिहाजा बच्चे बरामदे में पढ़ रहे हैं।

### स्कूल भवन की हालत है खस्ता

स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक नंदकुमार साय के मुताबिक स्कूल भवन की हालत इतनी खराब है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए चार साल से एक निजी भवन के बरामदे में स्कूल का संचालन हो रहा है।

प्रभारी प्रधानपाठक नंदकुमार साय के मुताबिक नवीन भवन को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों जनप्रतिनिधियों को आवेदन के माध्यम से मांग की गई। लेकिन आज तक शासन ने नए भवन को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। यहां पानी बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा का आभाव है। शासकीय भवन नहीं होनें की मजबूरी में हमें इस विद्यालय को संचालित करना पड़ रहा है।

### सरकार के दावों पर उठे सवाल

सरकार के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि गुलाब कमरों हर जगह विकास की दावे करते हैं।लेकिन उनके विधानसभा में ही प्राथमिक शाला का बुरा हाल है।बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर किसी को भी चिंता नहीं है।उसी का परिणाम है कि आत्मानंद विद्यालय का दंब भरने वाली सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि एक छोटे से स्कूल का उन्नयन किया जा सके।

# कोरबा में हाथियों ने रौंदी किसानों की फसलें, घर में घुसकर मचाया उत्पात

**कोरबा।** कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां के पसान रेंज में पड़ोसी जीपीएम जिले के मरवाही परिक्षेत्र से अचानक धमके हाथियों ने आधी रात को रेंज के पलामू कुम्हरी दर्री गांव में भारी कहर ढाते हुए आधा दर्जन ग्रामीणों के मकान को ध्वस्त कर दिया। वहीं, एक ग्रामीण के बाड़ी में पहुंचकर मकई की फसल को भी रौंद दिया। हाथियों का उत्पात यहां काफी देर तक चला। इस दौरान ग्रामीण हाथियों के डर से अपने-अपने घरों में छिपे रहे।

जानकारी के अनुसार वनमंडल कटघोरा के केंदई रेंज में 47 हाथी पहले से मौजूद हैं और लगातार उत्पात मचा रहे हैं। जिससे वन अमले के साथ-साथ क्षेत्रवासी परेशान हैं। मरवाही से पहुंचे हाथियों द्वारा आते ही उत्पात मचाए जाने से उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि केंदई व एतमानगर रेंज में अलग-अलग झुंडों में घूम रहे हाथी अब एक साथ एकत्रित हो गए हैं और केंदई रेंज के कापा नवापारा-कोयलारगडरा जंगल में डेरा डाल दिया है। जिससे हाथियों की निगरानी में आसानी हो रही है।

मरवाही रेंज से आए हाथियों ने पलामू गांव में जिन ग्रामीणों के मकान को निशाना बनाया, उनके नाम सितंबर सिंह पुत्र गंगा सिंह, दुर्गावती पत्नी सुखनंदन, राजू सिंह, शिवनारायण, अमर सिंह पुत्र रामधन और रामप्रसाद बताए गए हैं। इन लोगों ने परिवार समेत भागकर जान बचाई। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा रेंज में भी हाथियों द्वारा फसल रौंदे जाने का सिलसिला जारी है। यहां के कलमीटिकरा गांव में 25 और कुदमुरा बिट के धवन नाला जंगल में तीन हाथी घूम रहे हैं। हाथियों ने दोनों ही स्थानों में ग्रामीणों के खेतों में पहुंचकर धान की फसल को तहस-नहस कर दिया है।

हाथियों के उत्पात से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है। इससे पहले हाथियों ने बलबहरा व तरईमार में उत्पात मचाते हुए फसलों को तहस-नहस किया था।

# निर्वाचन के कार्यों को समय-सीमा में संपादित करें नोडल अधिकारी

**कोरबा।** कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों में संलग्न नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देशित किया कि सभी नोडल अधिकारी दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा बैठक में निर्वाचन कार्यों से जुड़े मानव संसाधन, प्रबंधन, प्रशिक्षण प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, कम्प्युटराइजेशन, साइबर सिक्योरिटी और आईटी, स्वीप नोडल अधिकारी, कानून व्यवस्था, ईव्हीएम मैनेजमेंट, एमसीसी नोडल अधिकारी, व्यय निगरानी, बैलेट पोस्टर-पेपर, एमसीएमसी, कम्युनिकेशन प्लान, मतदाता, शिकायत और मतदाता हेल्पलाइन आदि के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने निर्वाचन से संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक तैयारी के निर्देश देते हुए सेक्टर अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाम-निर्देशन के लिए आवश्यक तैयारी करने के साथ ही निर्वाचन से संबंधित कार्यों को भी समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने वाहन व्यवस्था, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने, मतदान केन्द्रों तक मतदान दलों को लाने ले जाने, डाकमत पत्र सेवा निर्वाचकों व मतदानकर्मियों को समय सीमा में प्रशिक्षण देने, निर्वाचन से संबंधित कार्य के लिए ड्यूटी लगाने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रेंडमाइजेशन करने, वीवीपैट के अभिलेखों का संधारण करने, मतदान दलों को प्रशिक्षण देने, मतदान सामग्री वितरण करने, प्रशिक्षण देने की जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर अधिकारी ने प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनिंग की व्यवस्था करने कहा।

**अरपा नदी में बच्चियों की मौत का मामला**

# हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर भी दर्ज कराएं

**बिलासपुर।** अरपा नदी सेंदरी में तीन बच्चियों की डूबने से मौत के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई शुरू की है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये निर्देश जारी किया है। अवैध खनन से हुए गड्ढों में भरे पानी में डूबकर सेंदरी के पास तीन बच्चियों की मौत हुई थी। साथ ही अवैध खनन और अरपा की दुर्दशा को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। प्रकरण में अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

बता दें, कि कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसके पहले मामले की सुनवाई के दौरान बीते 22 अगस्त को शासन से पूछा था, कि नदी में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर भी दर्ज कराएं, कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव और खनिज सचिव को शपथपत्र के साथ जवाब देने कहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एफआईआर के संबन्ध में पूछा तो पता चला, कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने इस मामले में चिन्हित चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हैं। दरअसल, बिलासपुर के सेंदरी के रेत घाट में बीते हरेली के दिन अरपा नदी में नहाने गई 3 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई थी, इस मामले में बच्ची के परिजन को 12 लाख रुपये मुआवजा देकर प्रशासन ने जिम्मेदारी पूरी कर ली। मामले की जांच या दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। जनहित याचिका में कहा गया है कि अरपा नदी में अवैध उत्खनन जानलेवा साबित हो रहा है। रेत उत्खनन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की भी खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। याचिका में अरपा के किनारे पौधरोपण करने, अवैध घाटों को बंद करने की मांग की गई है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिछली बार सुनवाई में खनिज विभाग की ओर से शपथपत्र में बताया गया कि, पिछले दो साल में 654 अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज हुए जिनमें पेनाल्टी लगाई गई है। 6 अवैध खनन के प्रकरणों पर कोनी थाने में एफआईआर भी दर्ज है। जिस पर कोर्ट ने अवैध खनन पर एफआईआर की कम संख्या होने को लेकर सवाल भी उठाए थे।

# बाजार में किसानों ने फेंके टमाटर तीन रुपये किलो का मिल रहा रेट

**बलरामपुर।** बलरामपुर जिले की शहर नगर पंचायत रामानुजगंज में दो महीने पहले टमाटर का रेट ढाई सौ से तीन सौ रुपय किलो तक पहुंच गया था। वहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार टमाटर के रेट में गिरावट आ रही थी। आज स्थिति ऐसी हो गई कि रामानुजगंज के थोक सब्जी बाजार में टमाटर का थोक रेट तीन रुपये किलो हो गया है। किसानों ने इससे हताश और निराश होकर टमाटर को बीच बाजार में फेंक दिया।

किसान मुकेश दास और सूरज धारकर ने बताया कि उन्होंने टमाटर की खेती करने में जितनी लागत लगाई थी। उन्हें उसका 20 प्रतिशत भी नहीं मिल रहा है। टमाटर तोड़ने में जितना खर्चा आया है, उसका भाव भी न मिलने से परेशान और निराश हैं। इसीलिए उन्होंने टमाटर को बीच रास्ते में फेंक दिया। क्षेत्र के दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों के द्वारा टमाटर का उत्पादन किया गया है, लेकिन लगातार टमाटर का मूल्य जहां दो अंको में आ गया था वहीं कुछ दिन पहले से एक अंक में आ गया है।

स्थिति ऐसी हो गई कि आज थोक सब्जी बाजार मे चार रुपये किलो टमाटर बिक रहा था, जिसमें एक रूपये किलो कमीशन में चला जाता है। इस प्रकार किसान को मात्र तीन रुपये किलो का ही मूल्य मिला। ऐसे में किसानों की हताशा और निराशा देखी सकती थी। कई किसान तो टमाटर को ऐसे ही छोड़कर चल दिए। वहीं, मुकेश दास और सूरज धारकर ने बीच बाजरा में ही टमाटर फेंक दिए।

**छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार**

### धार्मिक स्थल को असामाजिक तत्वों ने पहुंचाया नुकसान

**दुर्ग।** छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है।बावजूद इसके भिलाई में कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की। जिसकी जानकारी सुबह श्रद्धालुओं को हुई। श्रद्धालुओं ने इसकी जानकारी कॉलोनीवासियों को दी। कॉलोनीवासी मौके पर पहुंचे और फिर से धार्मिक स्थल को पहले जैसा था वैसा किया।इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई।असामाजिक तत्वों की इस हरकत से लोगों के बीच काफी गुस्सा है।अब श्रद्धालु आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है।सामाजिक संगठन ने घटना का विरोध करते हुए पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज करने के बाद क्षेत्र का दौरा किया। इसके बाद इलाके में पर्याप्त पुलिस बल लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरु की है।

### स्कूल में एयर बैलून सिलेंडर फटने से 33 बच्चे घायल

**सरगुजा।** शहर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूल के अंदर एयर बैलून सिलेंडर फटने से कई छात्र घायल हो गए हैं। स्कूल परिसर के अंदर हिंदू युवा मंच के लोग एयर बैलून में गैस भर रहे थे। इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जिस समय ये हादसा हुआ, उस दौरान स्कूल में लंच ब्रेक था। लिहाजा सैकड़ों बच्चे स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे। इसी दौरान हिंदू एकता युवा मंच के लोग स्कूल परिसर के अंदर एयर बैलून में गैस भर रहे थे। तभी सिलेंडर फट गया और 33 बच्चे घायल हो गए। बलून में गैस भरने वाले लोग भी घायल हुए हैं। इस घटना में घायल 11 बच्चों को चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में रखा गया है। 22 बच्चों का अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। गुब्बारा फुलाने वाली संस्था के सदस्यों का भी मिशन व निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। स्कूल में सिलेंडर फटने की खबर लगते ही कलेक्टर एसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। तेज आवाज के साथ सिलेंडर ब्लास्ट होने से बच्चे काफी डर गए हैं। बच्चों का रो रोकर बुरा हाल है।

### कोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी से मांगा जवाब

**बिलासपुर।** बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पीएससी-2022 के एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अरविन्द सिंह चन्देल की कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन और पीएससी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है और एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उनके मामले में जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों के इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जाहिर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया। इससे उनका चयन प्रक्रिया बाधित हुआ है।

### कार्य दलों की सम्पत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही जारी

**कोरबा।** विधानसभा निर्वाचन 2023 के संदर्भ में प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के परिपालन में 03 दिनों से निगम क्षेत्र में सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति में किए गए किसी भी प्रकार के सम्पत्ति विरूपण को हटाने तथा तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आयुक्त सु प्रतिष्ठा ममगाई ने जोनवार कार्य दलों को सम्पत्ति विरूपण को हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसके तहत निगम के गठित कार्य दलों द्वारा आज भी सम्पत्ति विरूपण को हटाने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार सम्पत्ति विरूपण के तहत सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का दीवाल लेखन, पोस्टर, पेपर, कट आउट, अवैध होर्डिंग, बैनर या अन्य किसी भी प्रकार से प्रचार सामग्री जो लगी हुई, उसे हटाने की कार्यवाही करने तथा सफाई एवं पोताई आदि करने हेतु आयुक्त सु ममगाई ने निगम में जोनवार कार्य दलों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

### तेंदुए की खाल की तस्करी तीन तस्कर गिरफ्तार

**मनेन्द्रगढ़।** मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुंवारपुर परिक्षेत्र में वन्यप्राणी तेंदुए की खाल की अवैध तस्करी करने के मामले में तीन आरोपियों को वन विभाग के उड़नदस्ता दल एवं वन कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। आरोपियों के पास से तेंदए की खाल और तस्करी में इस्तेमाल बाइक को जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल क्राइम लाईफ कंट्रोल ब्यूरो रायपुर को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग कुंवारपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर में चांग माता मन्दिर मार्ग पर संदिग्ध हालत मे खड़े हैं। जिनके पास वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल है और ये लोग इसे बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही उड़नदस्ता दल ने स्थानीय वन कर्मचारियों के सहयोग से कुंवारपुर परिक्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर परिसर के चांगदेवी माता मंदिर चौराहा के नजदीक सड़क पर बाइक के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़े मदन सिंह निवासी ग्राम खमरौध, पवन यादव ग्राम खमरोध, राजेन्द्र सिंह ग्राम भगवानपुर को पकड़ा गया।

# अपहरणकर्ता ने युवती को अगवा कर 15 लाख की फिरौती मांगी

■ **पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे**

**कोरबा।** कोरबा में अगवा कर फिरौती मांगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर से सिलाई सीखने के नाम पर निकली युवती रहस्यमयढंग से लापता हो गई थी। उसके दूसरे ही दिन से 15 लाख रुपए फिरौती मांगे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अपहरणकर्ता रकम नहीं देने पर युवती की हत्या कर शव घर भेजने की धमकी दे रहे हैं। मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है।

बांगों थानांतर्गत ग्राम पंचायत लेपरा के आश्रित ग्राम चुनभट्ठी में कृष्णा विश्वकर्मा रहते हैं। वह अपनी पत्नी और कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा था। कृष्णा ने बताया कि उसकी 28 वर्षीय बेटी संतोषी

सिलाई का काम सीखना चाहती थी। इसके लिए वह कोरबा में रहने वाली अपनी सहेली के पास तीन चार बार आ चुकी थी। वह 28 सितंबर की सुबह भी कोरबा के लिए रवाना हुई थी। वे हर बार की तरह शाम तक बेटी के घर लौट आने की उम्मीद में बैठे रहे, लेकिन संतोषी घर नहीं पहुंची। उसकी सहेली और नाते रिश्तेदारों में पूछताछ की गई तो कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी।

29 सितंबर को संतोषी के मोबाइल से एक कॉल आया। मोबाइल रिसीव करने पर किसी और की आवाज सुनाई दी। कॉल करने वाले ने संतोषी को अगवा कर लेने की जानकारी दी। उसने 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की। कथित अपहरणकर्ता ने रकम नहीं देने पर बेटी का कत्ल कर शव घर भेज देने की धमकी दी। यह सिलसिला बीते 12 दिनों से चला आ रहा है। कथित अपहरणकर्ता परिजनों के अलावा ग्रामीणों से भी संपर्क कर फिरौती की मांग कर रहा है। कृष्णा का कहना है कि उसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, जिसमें खेती किसानी कर मुश्किल से परिवार का भरण पोषण होता है। ऐसे में उसके लिए 15 लाख रुपए फिरौती दे पाना बेहद ही मुश्किल है। उसने अपनी बेटी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने की गुहार पुलिस के आला अफसर से लगाई है। मामले में बांगो पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।

### गुमशुदगी दर्ज कर औपचारिकता निभाती रही पुलिस

कृष्णा का कहना है कि उसकी बेटी 12 दिनों से लापता है। अपहरणकर्ता लगातार 15 लाख फिरौती के लिए धमकी दे रहे हैं। घटना के दूसरे ही दिन उसने मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी। आरोप है कि पुलिस सिर्फ गुमशुदगी दर्ज कर औपचारिकता निभाती रही है, जिससे हताश पिता को कोसों दूर सफर कर पुलिस मुख्यालय आना पड़ा। मामले को एएसपी अभिषेक वर्मा ने बताया की मामले को गंभीरता से लेते बांगो थाना मे जुर्म दर्ज किया गया है। और फोन डिटेल के आधार पर जांच की जा रही है।

# रंजना साहू के प्रत्याशी बनने पर लगातार चल रहा बधाई का सिलसिला

**धमतरी।** अपने उत्कृष्टता का प्रमाण देते हुए रंजना साहू ने धमतरी विधानसभा पर नए आयाम लिखे हैं, जनहित मुद्दों को सदन में सदैव सक्रियता एवं मुखरता से रखा जिसके फल स्वरुप विधानसभा में उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से सम्मानित किया गया और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर कार्य किए जिसके परिणाम स्वरूप धमतरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का भरोसा जीतते हुए पुन: धमतरी विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिससे विधानसभा क्षेत्र के भाजपाईयों में खुशी की लहर है, और अपनी लोकप्रिय मिलनसार व्यक्तित्व की धनी महिला सशक्तिकरण की पहचान श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू को बधाई देन घर पर एवं कार्यालय में पहुंच रहे हैं। शहरीय अंचल के साथ-साथ ग्रामीण अंचल व डुबान क्षेत्र से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस खुशी के मौके पर शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए कहां है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं और अपना बूथ सबसे मजबूत के सिद्धांत पर कार्य करने का आव्हान किए।

# संक्षिप्त समाचार

## विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समाज ने मांगी टिकिट

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समाज की बैठक हनुमान मंदिर में संपन्न हुई जिसमें उपस्थित समाज के वरिष्ठजनों ने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों से ब्राम्हण प्रत्याशी को टिकिट दिए जाने की मांग कांग्रेस आलाकमान से की है। संपन्न हुई बैठक में वरिष्ठजनों ने अपने मत और विचार रखते हुए कहा कि ब्राम्हण समाज ने हमेशा समाज सेवा के कार्यों के अलावा दिगर क्षेत्रों में भी अन्य वर्गों के लिए कार्य करते आ रहे है, ऐसे में इस समाज को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। समाज के वरिष्ठ जनों ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से ब्राम्हण प्रत्याशी के रुप में प्रमोद दुबे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग है। बैठक में लगभग 200 से अधिक समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे।

## छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दशहरा और दिवाली पर 6-6 दिन की छुट्टी

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। कुल 64 दिनों तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस महीने से त्योहारी छुट्टी शुरू हो गई है। दशहरा पर 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इसके बाद नवंबर में दिवाली पर 11 से 16 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। अवकाश को लेकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिल रही है। विभागीय आदेशानुसार प्रदेश में 64 दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रदेश में 23 अक्टूबर से छुट्टी शुरू हो जाएगी। दशहरे पर स्कूलों में 23 से 28 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। दीपावली पर 11 नवंबर से 16 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा शीतकालीन 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक छुट्टी रहेगी। इसके बाद ग्रीष्मकालीन छुट्टी 1 मई 2024 से 15 जून 2024 तक स्कूलों में में छुट्टी रहेगी।

## शारदीय नवरात्रि 15 से, तैयारियां अंतिम चरणों में

**रायपुर।** शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है और मंदिरों के साथ ही पंडलों में तैयारियां अतिम चरण में है। इस दौरान पूरे प्रदेश में 23 अक्टूबर तक भक्तिमय माहौल बना रहेगा और 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस साल विशेष पूजा के लिए भी मंदिरों में व्यवस्था की गई है। प्रथम दिवस, पंचमी और अष्टमी में मंदिरों में विशेष पूजा की जाएगी। मां बम्लेश्वरी, दंतेश्वरी, रायपुर और बिलासपुर की माँ महामाया, महासमुंद की चंद्रहासिनी, धमतरी की बिलाई माता के साथ ही अन्य मंदिरों में भी तैयारी अंतिम चरणों में है। पदयात्रियों के लिए विशेष मार्ग तैयार किया गया है।

## गागड़ा के ग्रामीणों ने किया कांग्रेस प्रवेश

**कोंडागांव।** कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से गठबंधन करने वाले 10 से अधिक कट्टर कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। मोहन मरकाम की नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के विकास कामों की सराहना करते हुए मोहन मरकाम को विधायक बनाने का समर्थन किया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की स्थापना करने की आशा व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि जेपी यादव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अमित गुप्ता, एल्डरमेन नरेंद्र देवांगन, हरेंद्र पांडे उपस्थित थे।

## 12495 लाइसेंसी हथियारों में से जमा किए गए 8807

**रायपुर।** राज्य में आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाइसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी की गई है। 12495 लाइसेंसी हथियारों में 8807 जमा किये गये हैं। 3 जब्त किये गये हैं और 10 कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1229 प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत 1284 हथियार जब्त किये गये हैं। 54 लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत 3 लाख 64 हजार 86 प्रकरणों में 18 करोड़ 49 लाख 4 हजार 157 रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत 1 लाख 34 हजार 206 प्रकरणों मे 1 लाख 81 हजार 527 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा 1 लाख 5 हजार 863 बाउंड ओवर किये गये हैं। आबकारी मामलों में 19 हजार 891 केस दर्ज किये गये हैं इसमें 1 लाख 29 हजार 48 लीटर की 5 करोड़ 28 लाख 85 हजार 758 रुपए की शराब जब्त की गई है।

## सरकारें आई और गई पर नहीं मिला रायगढ़ को रेल टर्मिनल

**रायगढ़।** कई सरकारें आई और गई केंद्र में भी परिवर्तन हुआ राज्य में भी परिवर्तन हुआ परंतु रायगढ़ को इंसाफ नहीं मिला, मिला तो सिर्फ आश्वासन और मिले तो केवल कोरे वादे। सन 1998 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने यहां रेलवे कोचिंग टर्मिनल का शिलान्यास किया था। जिसके लिये भूमि भी उपलब्ध हो गयी परंतु यह मांग आज तक लंबित है। 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व भी सभी जनप्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स रायगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल एवं महामंत्री हीरा मोटवानी के नेतृत्व में चेंबर के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से यह मांग रखी थी कि रायगढ़ में हवाई सुविधा के लिए प्रस्तावित एयरपोर्ट और विभिन्न यात्री गाडियों के परिचालन को बल देने के लिए रेलवे कोचिंग टर्मिनल की स्थापना की जावे ।

# कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में खाया भ्रष्टाचार का कैंडी : श्रीवास्तव

**रायपुर।** प्रसार भारती के दूरदर्शन समाचार द्वारा बुधवार को छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दौरों के दौरान वे हेलीकॉप्टर में शोर के कारण चर्चा नही हो सकती और इंटरनेट भी नही रहता इसलिए वे कैंडी क्रश गेम खेलते हैं। इस कटाक्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की कैंडी खा रही और जनता से जुड़े विकास कार्यों को क्रश कर रही हैं और अब जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। पत्रकारवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री मोहन मरकाम, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम का मुखौटा पहनकर भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए।

शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव एप जैसे मामलों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में पत्रकारवार्ता के दौरान श्रीवास्तव ने कहा कि मोहन मरकाम को हटाकर उन्हें महज दो-

तीन महीने के लिए ही मंत्री बनाया, ढाई-ढाई साल का वादा करके टीएस सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री और पद छीन कर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम को योजना आयोग दे दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, रेत घोटाला, कोल घोटाला, पीएससी घोटाला और ऑनलाइन सट्टा जैसे मामलों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करके खूब कैंडी खाई है और आने वाले दिनों में मतदाता कांग्रेस को माफ नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि ये डुप्लीकेट मंत्री जो खड़े है ये चीजें हैं वो बाहर आना चाहिए. वो इसलिए है कि कांग्रेस कार्यालय में यदि बैठक होती है और फोटो वायरल होता है तो कहा जाता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ से फोटो दिया. जो भी होगा कांग्रेस का कार्यकर्ता एक फोटो देगा तो वह बाहर को आएगा ही। तब बीजेपी ने इसे संज्ञान में लिया। अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करें तो वह हेलीकाप्टर में कैंडी क्रैश खेलते है, यह उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है लेकिन यह खेल विदेशियों द्वारा बनाया गया है, अगर मुख्यमंत्री को खेलना ही था वे लूडू व अन्य खेलते कैंडी क्रैश ही क्यों। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे है और पिछले पांच सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने कैंडी क्रेश के माध्यम से खाया है। लेकिन जनता अब इसका जवाब अपने मताधिकार का प्रयोग करके जरुर देगी।

# प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम

**रायपुर।** विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता हेतु सामान्य स्वीप गतिविधियों के आयोजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर स्वीप कार्ययोजना अंतर्गत मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में उल्लेखित है कि स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु तत्काल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एक स्वीप नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवप्रवेशित नये छात्र-छात्राओं को मतदान प्रक्रिया से जोडने हेतु प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाये जिसमें कैम्पस एम्बेसडर एवं प्रोफेसर नोडल अधिकारी (स्वीप) का विशेष सहयोग लिया जाए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर संचालित अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक नारों को शासकीय कार्यालयों की दीवारों पर खाली स्थानों में सुंदर लिखावट में प्रदर्शित किया जाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/ स्टेट आईकन के संदेशों का रिकार्डेड मेसेज (ऑडियो-विडियो) का प्रसारण स्थानीय सिनेमाघरों, स्थानीय केबल टीवी, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाए। साथ ही ग्रामीण इलाकों एवं हाट बाजारों में कोटवार के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं यथा मतदान तिथि, मतदान समयावधि तथा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का मुनादी के माध्यम से प्रचार कराया जाये।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं जिसके अंतर्गत संगवारी मतदान केंद्रों, सभी महिला कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम दस), दिव्यांग कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केन्द्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक), सभी युवा प्रबंधित मतदान केंद्र (प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक ), आदर्श मतदान केन्द्र- उपरोक्त में से किन्ही 5 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र का स्वरूप प्रदान किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया गया है।

# हरदिहा साहू समाज हुआ भाजपा से खफा, आस अब कांग्रेस से

■ **मोतीलाल का स्वागत, नंदे को भी देना था टिकट**

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी ने 85 विधानसभा सीटों के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है जिसमें से हरदिया साहू समाज से एक भी को टिकट नहीं दिए जाने समाज के लोगों में काफी आक्रोश है और नामांकन से पहले समाज के दो-तीन लोगों को टिकट देने की मांग कर रहे है लेकिन उन्हें उम्मीद कम ही लग रहा है। अब उनकी आस कांग्रेस पार्टी से क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अगर दोनों ही पार्टी उनके समाज को टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में मैदान में उतरेंगे। भाजपा ने रायपुर ग्रामीण से झेरिया साहू समाज के मोतीलाल साहू को प्रत्याशी घोषित किया है उसका समाज स्वागत करता है लेकिन हरदिहा साहू समाज से पूर्व विधायक नंदकुमार साहू को भी टिकट दिया जाना चाहिए था।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए समाज के प्रदेश संरक्षक सोमनाथ साहू, महानंद साहू, राजेश साहू व अन्य लोगों कहा कि प्रत्याशी घोषित करने से पहले हरदिहा साहू समाज का प्रतिनिधिमंडल भाजपा

अध्यक्ष अरुण साव से मिलकर रायपुर ग्रामीण, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, साजा, बालोद, धमतरी, पाटन, मंदिरहसौद, धरसींवा से टिकट देने की मांग की थी लेकिन भाजपा ने समाज के किसी भी लोगों को टिकट नहीं दिया था जिससे वे खफा है। उनकी मांग की है कि नामांकन से पहले रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार में प्रत्याशी बदलकर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए लेकिन उम्मीद कम ही है। इसलिए अब उनकी आस कांग्रेस पार्टी से क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी से वे दो विधानसभाओं में टिकट की मांग की है अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देता है तो कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रुप से सहयोग करेगा। अगर समाज टिकट नहीं दिया जाता है तो समाज के लोग दोनों ही पार्टियों को समर्थन नहीं करेगी और अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और इससे 12 विधानसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियों को नुकसान होगा।

# कांग्रेस के गढ़ सीतापुर में खिलेगा कमल : टोप्पो

■ **मंत्री अमरजीत भगत पर भाजपा प्रत्याशी का तंज**

**अंबिकापुर।** छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासत गरमाई गई है। सरगुजा संभाग में छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी सीट है, जहां से कांग्रेस आज तक कभी नहीं हारी है। इसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा सीट की। जहां से वर्तमान में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विधायक हैं। लेकिन अब सियासी गलियारों में एक नाम और आ गया है, जो अमरजीत भगत खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा है। जिससे क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई है।

चुनावी बिल्कुल बजाने के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान रामकुमार टोप्पो को लेकर सवालों पर मंत्री भगत ने कहा, कोई भी पार्टी अपना सीट खाली नहीं छोड़ती। किसी न किसी को खड़ा करती है। चुनाव एक चुनौती है, जिसका सामना हम बखूबी करते हैं। यहां की जनता एक

बार फिर से कांग्रेस को ही काम करने का मौका देगी। मंत्री अमरजीत भगत ने पांचवी बार चुनाव जीतने का दावा किया है।

सीतापुर से लगे गांव मैनपाट, जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। जहां पहले ना तो सड़क संसाधन की सुविधा थी और ना ही पर्यटन के लिए कोई सुविधा थी। लेकिन मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इन पांच सालों में सभी सुविधाएं मुहैया कराई है। जैसे मैनपाट कार्निवाल का आयोजन, करमा महोत्सव, आदिवासी दिवस, खेल महोत्सव। इन तमाम कार्यक्रमों में देश-विदेश के कलाकारों को यहां की जनता को देखने का अवसर मिला, जो पहले नहीं मिलता था। यहां की जनता में काफी उत्साह देखने को मिला है। इन्हीं उत्साहों से हमें जीत की खुशबू आ रही है।

मंत्री अमरजीत भगत के गढ़ को भेदने के लिए भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो ने कमर कस ली है। रामकुमार टोप्पो ने भी सीतापुर में बीजेपी के जीत का दावा करते हुए कहा, चुनावी बिगुल बज चुका है और पार्टी ने मुझे नहीं तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। इस बार का चुनाव भाजपा नहीं, सीतापुर की तमाम जनता लड़ रही है। निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली हाई प्रोफाइल सीट सीतापुर में कमल खिलेगा।

बता दें कि 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे।

# रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस से 7 दावेदार 15 अक्टूबर को घोषित होने की संभावना

**राजनांदगांव।** राजनांदगांव विधानसभा सीट पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से इस बार 7 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है क्योंकि पिछले डेढ़ दशक से इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। भाजपा ने इस बार फिर डा. रमन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं कांग्रेस ने अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और संभवत- 15 अक्टूबर को पहली सूची जारी होने की संभावना है। उसमें पता चल पाएगा कि रमन सिंह के खिलाफ भागवत साहू, महापौर हेमा देशमुख, कुलबीर छाबड़ा, जितेंद्र मुदलियार, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया या युवा चेहरा निखिल द्विवेदी चुनाव लड़ेंगे।

साहू समाज के मतों का ध्रुवीकरण के चलते साहू समाज के जिलाध्यक्ष और हाल ही में कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भागवत साहू का नाम सामने आ रहा है। साहू समाज के उम्मीदवार को मौका देकर अन्य

विधानसभा क्षेत्रों में भी कांग्रेस प्रभाव डालने की कोशिश कर सकती है। वहीं महापौर हेमा देशमुख भी एक सशक्त दावेदार मानी जा रही है और लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय भी है। शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा भी दमदार चेहरे हैं और 5 बार के पार्षद छाबड़ा ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वार्ड से भाजपा को मात दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुलबीर की साख मजबूत है। युवा आयोग अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार की लोकप्रियता भी बरकरार है उन्हें युवाओं के बीच दमदार चेहरा माना जा रहा है। वे पूर्व विधायक स्व. उदय मुदलियार के बेटे हैं । पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने भी दावेदारी पेश की है क्योंकि उन्होंने बतौर महापौर राजनांदगांव को अलग पहचान दिलाया था। युवा चेहरे निखिल द्विवेदी भी टिकट के दौड़ में शामिल है और वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि टिकट घोषणा के समय इन चेहरों में से कौन उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे।

# राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल में बस्तर, बिलासपुर रायपुर व दुर्ग ने जीते अपने प्रारंभिक मैच

**रायपुर।** उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन गुरुकुल महिला महाविद्यालय द्वारा साई सेंटर आउटडोर स्टेडियम में किया गया है। इस प्रतियोगिता में 10 सेक्टर सरगुजा, बस्तर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार -महासमुंद, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर एवं बिलासपुर टीम ने अपनी भागीदारी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजय तिवारी अध्यक्ष, शासी निकाय गुरुकुल महिला महाविद्यालय ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर बिगुल बजाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की।

कार्यक्रम में श्रीमती शोभा खंडेलवाल ,सचिव भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति, प्राचार्य डॉ संध्या गुप्ता, श्री के सी त्रिपाठी साईं प्रभारी, रेनू साईं कोच ने अपनी उपस्थिति देकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। क्रीडा प्रतियोगिता की आयोजन डॉ रिंकू पांडे ने किया।वॉलीबॉल का पहला प्रतियोगिता सेक्टर सरगुजा और बस्तर के बीच हुआ जिसमें सेक्टर बस्तर की टीम विजेता रहे। दूसरा प्रतियोगिता सेक्टर बिलासपुर और जांजगीर के बीच हुआ जिसमें सेक्टर बिलासपुर की टीम विजेता रहे। तीसरा प्रतियोगिता सेक्टर रायपुर और रायगढ़ के बीच हुआ जिसमें सेक्टर रायपुर की टीम विजेता रहे।चौथा प्रतियोगिता सेक्टर कोरबा और दुर्ग के बीच हुआ जिसमें सेक्टर दुर्ग की टीम विजेता रहे। इस आयोजन में विभिन्न महाविद्यालयों के क्रीड़ाधिकारी मौजूद रहे।

# विधानसभा चुनाव में बिल्हा विधानसभा की अहम भूमिका

**बिलासपुर।** बिलासपुर जिले की बिल्हा विधानसभा सीट प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट माना जाती है। बिल्हा विधानसभा प्रदेश के हाईप्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां बीते कई कार्यकाल से भाजपा के दिग्गज नेता धरमलाल कौशिक चुनाव लड़ते आए हैं। वर्तमान में भी इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा के दिग्गज नेता धरमलाल कौशिक यहां से विधायक हैं और इस बार भी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है।

विधायक रहते हुए धरमलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन बिल्हा विधानसभा सीट की एक तासीर ये भी है कि यहां की जनता दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा को बराबर मौका देती है। यहां भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने ही राज किया है। बिल्हा विधानसभा दो जिलों का सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र है। बिलासपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ मुंगेली जिले का पथरिया और सरगांव ब्लॉक का इलाका भी इसी विधानसभा में आता है।

बिल्हा विधानसभा में कुल 305982 मतदाता हैं। इनमें

से 151943 महिला और 154027 पुरुष मतदाता हैं। वहीं, 8905 युवा मतदाता हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल है। बिल्हा विधासभा में कुल आबादी करीब साढ़े चार लाख है। एससी और आदिवासी वोटर्स की यहां बड़ी मौजूदगी है। यह ओबीसी बाहुल विधानसभा है। इसमें करीब 45 फीसदी ओबीसी वर्ग के वोटर्स हैं। जिसमें कुर्मी, साहू, लोधी और यादव शामिल हैं। वहीं, करीब 25 फीसदी हरिजन व आदिवासी और 30 फीसदी ठाकुर-ब्राह्मण वोटर हैं।

1962 से 1985 तक लगातार कांग्रेस के चित्रकांत जायसवाल ने यहां पर पार्टी का झंडा बुलंद किया, लेकिन 1990 में अशोक राव ने कांग्रेस से बगावत की और जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़कर यहां कांग्रेस के चित्रकांत जायसवाल को मात दी। हालांकि 1993 में अशोक राव दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए और बीजेपी के धरमलाल कौशिक को हराया। 1998 में पहली बार यहां से धरमलाल कौशिक ने बीजेपी का झंडा बुलंद किया, लेकिन 2003 में वे अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे। उन्हें कांग्रेस के सियाराम कौशिक ने मात दी।

2018 के चुनाव में फिर समीकरण बदले। कांग्रेस का दामन छोड़कर सियाराम कौशिक जोगी कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरे, जिसके जवाब में कांग्रेस ने राजेंद्र शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा के धरमलाल कौशिक एक बार फिर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। बीजेपी के धरमलाल कौशिक को 84,431 वोट मिले। वहीं, कांग्रेस के राजेंद्र शुक्ला को 57,907 वोट मिले। पूर्व विधायक व जोगी कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक करीब 31 हजार वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इस जीत के बाद भी प्रदेश में भाजपा के हार का ठीकरा तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे धरमलाल कौशिक पर भी फूटा। हालांकि, इसके बाद भी धरमलाल कौशिक को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली। धरमलाल कौशिक बतौर नेता प्रतिपक्ष मोर्चा संभाला। धरमलाल कौशिक को डॉ. रमन सिंह का करीबी और विश्वस्त माना जाता है।

बिल्हा विधानसभा के सियासी तासीर के साथ यहां कई ज्वलंत मुद्दे भी हैं। बिल्हा विधानसभा में पिछड़े आदिवासी गांव हैं तो चमचमाती सड़कों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले शहरी क्षेत्र भी यहां मौजूद हैं। यहां सिरगिट्टी, तिफरा जैसे औद्योगिक इलाके हैं तो यदुनंदन नगर से लेकर चकरभाठा तक कई बड़ी कॉलोनियां भी हैं। बिलासपुर नगर निगम के कुछ वार्ड भी बिल्हा विधानसभा में आते हैं। सीमावर्ती मुंगेली जिले का पथरिया, सरगांव भी इसी विधानसभा में है। यहां बुनियादी समस्याओं के अलावा पेयजल, सिंचाई व्यवस्था और सरकारी योजनाओं का ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं होना व अवैध उत्खनन भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस यहां से किसी नए उम्मीदवार को मौका दे सकती है। तीसरे मोर्चे के तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी यहां से पार्टी के कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है।

# ओबीसी कार्ड का लाभ किसे

**विजय विद्रोही**

राहुल गांधी के पास क्या गेम चेंजिंग आइडिया आ गया है? भले ही इंडिया गठबंधन के सभी दल जातीय जनगणना के पक्ष में न हों, पर राहुल गांधी इसे मुख्य चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना की गारंटी दी जा रही है। यहां तक कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने भी अपने अधिकारियों को बिहार के अधिकारियों से जातिगत जनगणना की प्रक्रिया की जानकारी लेने को कहा है। असम के मुख्यमंत्री सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर चुके हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक जातिगत सर्वे करवा चुके हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पास ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट तैयार पड़ी है, जिसे उचित समय में सार्वजनिक करने की बात की जा रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जातीय सर्वे की घोषणा तो कर ही चुके हैं, राहुल गांधी की मौजूदगी में ओबीसी का आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 26 करने का एलान भी कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार सरकार की अगली रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। उसमें पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, किस पद पर हैं, निजी क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग हैं, कितनों के पास कार-मोटरसाइकिल या साइकिल है और कितनों के पास कितनी जमीन है। इससे यह भी पता चलेगा कि सुशासन बाबू के राज में सामाजिक न्याय की दिशा में कितना काम हुआ, महादलितों, महापिछड़ों और पसमांदा मुस्लिमों की आर्थिक हालत कैसी है? नीतीश कुमार इसे समझ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि सर्वे कराने का मकसद राजनीति करना नहीं, बल्कि ओबीसी की वास्तविक संख्या का पता लगाकर उसके हिसाब से विकास की योजनाएं बनाना है। यही बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि ओबीसी जनगणना को युवा ओबीसी को मिले रोजगार के मौकों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से जोड़ना है। पढ़ाई और नौकरी युवा ओबीसी को लंबे समय तक %इंडिया% से जोड़े रख सकती है। कांग्रेस समझ रही है कि उसे सत्ता में आना है, तो अपने वोट बैंक में भारी-भरकम इजाफा करना है। ऐसा वोट बैंक महापिछड़े ही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 15 फीसदी ओबीसी वोट, जबकि भाजपा को 44 फीसदी ओबीसी वोट मिला था। यहां तक कि सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों के हिस्से में भी 41 फीसदी ओबीसी वोट ही आया था। जबकि 1996 में भाजपा को 21 फीसदी, सामाजिक न्याय वाले दलों को 54 फीसदी और कांग्रेस को 24 फीसदी ओबीसी वोट मिला था। ये आंकड़े ही बता देते हैं कि क्यों राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की जरूरत है। इस हिसाब से आगामी दिसंबर से देश में सियासत करने का तरीका बदलने वाला है। अगर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जीत हासिल की, तो ऐसा नरैटिव स्थापित किया जाएगा, जैसे यह ओबीसी वोट की गोलबंदी से हुआ है। वैसी स्थिति में जातीय सर्वे की घोषणा कर दी जाएगी। आगामी जनवरी में जब भाजपा अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह करवा रही होगी, तब इंडिया के भीतर से ओबीसी सर्वे की मांग उठ रही होगी। बिहार का सर्वे सामने आया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विपक्ष का पाप बताया। मोदी ने अगले दिन गरीब को सबसे बड़ी जाति बताया, तो कांग्रेस पर मुसलमानों का हक छीनने का अजीब-ओ-गरीब आरोप जड़ दिया।

# जातीय जनगणना के एजेंडे में फंसे राहुल

**अजय सेतिया**

कांग्रेस ने अपने पूरे इतिहास को कूड़ेदान में फेंक कर जाति आधारित जनगणना को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। पहले 16 सितंबर को हैदराबाद की कांग्रेस कार्यसमिति में जातीय जनगणना करवाने का प्रस्ताव पास किया गया। बाद में 9 अक्टूबर को दिल्ली की कार्यसमिति में जाति आधारित जनगणना को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया गया। इस बीच राहुल गांधी ने कई मंचों पर घोषित कर दिया था कि जाति आधारित जनगणना और उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला तय किया जाएगा।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं ने चुनावों के बाद सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना का वादा 9 अक्टूबर की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक से पहले ही करना शुरू कर दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो एक कदम आगे बढ़कर कार्यसमिति की बैठक से कुछ घंटे पहले 8 अक्टूबर को जाति आधारित सर्वे का नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया। हालांकि 9 अक्टूबर को जब कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक चल रही थी, तब चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी, और अब आचार संहिता लग जाने के बाद यह नोटिफिकेशन सिर्फ चुनावी मुद्दा बन कर ही रहेगा, जैसे दूसरे राज्यों में चुनावी मुद्दा होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में माना कि 2018 के चुनाव तक चली उनकी पिछली सरकार ने 2014-15 में जाति आधारित सर्वे करवा कर उसकी रिपोर्ट अलमारी में बंद करवा दी थी, उसे अब जारी किया जाएगा।

कांग्रेस ने जब जाति आधारित जनगणना का राग अलापना शुरू किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस में अब सोचने समझने वाले नेता नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस ने नीतियाँ बनाने का काम आऊटसोर्स करना शुरू कर दिया है। उनके कहने का मतलब यह था कि हिन्दू समाज को जातियों में विभाजित करने का फार्मूला कांग्रेस ने लालू यादव और नीतीश कुमार से उधार लिया है, जो 1989 से ही जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे नेताओं के दबाव में ही वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके इन सब नेताओं के हाथ में जातिवादी राजनीति का हथियार सौंपा था। जबकि कांग्रेस ने ऐसी किसी भी रणनीति और नीति का हमेशा विरोध किया, जो देश और समाज को जाति या धर्म के आधार पर टुकड़ों में बांटती हो। अंग्रेजों ने जब 1931 में जाति आधारित जनगणना करवाई थी, तो कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इस तर्क के साथ जाति आधारित जनगणना का विरोध किया था कि इससे समाज का तानाबाना बिगड़ जाएगा। 1931 के जनगणना के बाद देश को धर्म के नाम पर बंटवारे की जो मुहिम मुस्लिम लीग ने शुरू की थी, उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से पंजाब, सिंध, ब्लूचिस्तान, नार्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल को अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी थी। इसी बीच बिहार में त्रिवेणी संघ यादव, कोईरी और कुर्मी जातियों का गठबंधन भी राजनीतिक हलचल मचाए हुए था। जाति की आबादी के आधार पर दबदबे की लड़ाई में कांग्रेस को बड़े खतरे की आहट दिखाई दी। इसलिए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि वह 1941 की जनगणना जाति आधारित न करे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 की आधी अधूरी जनगणना हुई, जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए। आज जो नारा राहुल गांधी लगा रहे हैं, वह पहले डॉ. अम्बेडकर और बाद में कांशीराम लगा चुके है, लेकिन दोनों ही बार कांग्रेस ने इस नारे का विरोध किया था। आज़ादी के बाद डॉ. अम्बेडकर ने जब यह कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो जवाहर लाल नेहरू ने 1951 में यह कहते हुए जाति आधारित जनगणना करवाने से इंकार कर दिया था कि इससे समाज में बिखराव हो जाएगा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने योजनाबद्ध तरीके से अंबेडकर को 1952 का लोकसभा चुनाव हरवाया, फिर 1953 का उपचुनाव भी हरवाया। जवाहर लाल नेहरू ने मंत्रीमंडल के भीतर से दबाव पड़ने पर ओबीसी जातियों की पहचान के लिए काका कालेलकर आयोग बनाया था। इस आयोग ने 1955 में दी अपनी रिपोर्ट में 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की। लेकिन जवाहर लाल नेहरू ने रिपोर्ट में खामियां बताकर सिफारिश की फाईल कूड़ेदान में फेंक दी। इसका कारण यह था कि कांग्रेस का आधार अगड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों में था। उसने बहुसंख्यक पिछड़ी जातियों की कभी परवाह ही नहीं की। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 1978 में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग का गठन किया था। जनता पार्टी की इस सरकार में भाजपा (जनसंघ के रूप में) भी शामिल थी। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें इंदिरा गांधी सरकार को सौंपी थी। तो उन्होंने पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सिफारिश वाली मंडल आयोग की फाईल कूड़ेदान में फेंक दी। 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर रहे थे, तो राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाली सिफारिशों को लागू करने का विरोध किया था। जबकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उस समय उन्हें समझाया था कि आरक्षण का विरोध कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा। वही हुआ भी, उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति आधारित राजनीति के चलते कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया। पिछड़ों में सबसे ज्यादा प्रभाव रखने वाले यादवों ने इन दोनों ही राज्यों में उन्हें आरक्षण दिलाने वाले अपने जातीय नेताओं के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंप दी। जिस कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने के लिए जाति आधारित राजनीति का हमेशा विरोध किया, सत्ता गवां कर भी विरोध जारी रखा, वही कांग्रेस अब उन्हीं जातिवादी नेताओं के चंगुल में फंस कर जाति आधारित जनगणना को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रही है। जाति आधारित जनगणना का मकसद यह है कि 1931 की जनगणना के आधार पर 1990 में दिया गया 27 प्रतिशत आरक्षण का कोटा, उनकी मौजूदा जनसंख्या के आधार पर बढ़ना चाहिए। 1931 की जनगणना में ओबीसी 52 प्रतिशत थे, उसी आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। जैसे अब बिहार की जातीय जनगणना ओबीसी 27.7 प्रतिशत, अति पिछड़े 36.1 प्रतिशत निकले हैं, यानि उनकी कुल संख्या 63.8 प्रतिशत है। लेकिन इन आंकड़ों में मुस्लिम भी है, बिहार में 17.7 प्रतिशत मुस्लिम हैं, और इन 17.7 प्रतिशत में से 70 प्रतिशत पिछड़े हैं, जिन्हें पिछड़ों को मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जाति आधारित जनगणना या ओबीसी के लिए आरक्षण बढाना कभी भी कांग्रेस और राहुल गांधी के एजेंडे पर नहीं था। असल में पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, इसे भाजपा ने उन्हें ओबीसी विरोधी नेता के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। अदालत ने इसी आधार पर उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि सभी मोदियों को चोर कह कर उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समाज हैं।

राहुल गांधी के कन्विक्शन पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक जरुर लगाई है, उन्हें बरी नहीं किया है। ओबीसी समाज के अपमान का दाग अभी भी उनके चेहरे पर चिपका हुआ है। इसलिए जब इंडी एलायंस की मुम्बई बैठक में लालू यादव और नीइश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को इंडी एलायंस के एजेंडे पर रखने का प्रस्ताव रखा, तो एलायंस में विरोध के बावजूद राहुल गांधी ने इसे लपक लिया। कम से कम चार नेताओं के विरोध के बावजूद पहले इसे को-आर्डिनेशन कमेटी से पास करवा कर इंडी एलायंस का एजेंडा घोषित कर दिया, और बाद में कांग्रेस ने इसे अपने एजेंडे पर ले लिया। 9 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या जाति आधारित जनगणना पर इंडी एलायंस में सहमति है, तो उन्होंने कहा कि दो-चार दल अगर इसके खिलाफ भी होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस फासीवादी पार्टी नहीं है। सवाल यह है कि क्या चुनावों में जाति आधारित जनगणना का कांग्रेस और जाति आधारित अन्य राजनीतिक दलों का कार्ड भाजपा पर भारी पड़ेगा। क्या पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिला 44 प्रतिशत पिछड़ों का समर्थन घट जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर चुनावों में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हावी हो जाता है, तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा या जाति आधारित उन राजनीतिक दलों को होगा, जिन्होंने कांग्रेस को जाति आधारित जनगणना को मुद्दा बनाने को मजबूर किया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी देवेगौडा ने एनडीए में शामिल होने के बाद एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस उन्हीं जाति आधारित राजनीतिक दलों के जाल में फंस गई है, जिन्होंने जाति आधारित राजनीति करके कांग्रेस को कमजोर किया। अब इसका मतलब तो यही है कि कांग्रेस को नहीं, उन्हीं दलों को ही फायदा होगा, जो अब तक ओबीसी की राजनीति करते आए हैं।

**भारतीय ज्ञान परंपरा....**

# महोपनिषद् (भाग-14)

**गतांक से आगे...**

शरीर पर सतत बाणों के समूह का आघात, गर्मी को शान्त करने वाले फव्वारे के जलकणों की वर्षा के सदृश बन जाता है। सिर का काटा जाना, सुखप्रदायिनी निद्रा के समान (जिह्वा आदि काटकर) गूँगा हो जाना, मौनावलम्बन के समान बधिर हो जाना, उन्नति के समान सुख प्रदायी होता है; लेकिन यह अवस्था उपेक्षा करने से नहीं मिलती। इसकी प्राप्ति दृढनिश्चयी होकर वैराग्यजनित आत्मज्ञान से ही सम्भव है। गुरु एवं शास्त्र वचनों के अनुसार तथा अन्त: अनुभूति के माध्यम आदि से जो अन्त: की शुद्धि होती है, उसी के सतत अभ्यास से आत्म-साक्षात्कार किया जा सकता है।

जैसे दिशा- भ्रम नष्ट हो जाने से पूर्व की भाँति ही दिशाबोध होने लगता है, वैसे ही विज्ञान (विशिष्ट (ज्ञान) के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाने पर जगत् की स्थिति नहीं रहती, ऐसी भावना करनी चाहिए। मनुष्य का उपकार न धन से, न मित्रों से, न बान्धवों से न शारीरिक क्लेश के नष्ट होने से और न ही तीर्थ स्थल में निवास करने से ही मनुष्य लाभान्वित होता है; वह तो चिन्मात्र में विलीन होकर ही परमपद प्राप्त कर सकता है।

स्थिर शान्तचित्त वाले व्यक्तियों के जितने भी दु:ख, तृष्णायें एवं दु:सह दुश्चिन्तायें हैं, वे और समस्त विकार ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य की किरणों से अन्धकार विनष्ट हो जाता है। इस नश्वर जगत् में शम (मनोनिग्रह) से युक्त मनुष्य का कठोर एवं मृदु स्वभाव के समस्त प्राणी-जन वैसे ही विश्वास करते हैं, जैसा माता पर उसके पुत्र विश्वास करते हैं। अमृत पान एवं लक्ष्मी के आलिङ्गन से वैसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा सुख व्यक्ति अपने मन की शान्ति से प्राप्त करता है। शुभ एवं अशुभ के श्रवण से, भोजन से, स्पर्श से, दर्शन से एवं जानने से, जिस मनुष्य को न तो प्रसन्नता होती है और न ही दु:ख होता है, वही मनुष्य शान्त कहलाता है। चन्द्रमा के मण्डल की भाँति जिसका मन सदा स्वच्छ रहता है एवं मरण-काल, मांगलिक उत्सव तथा युद्ध में जिसका मन व्यग्र नहीं होता, वही मनुष्य शान्त कहलाता है। वह (शम प्रधान) पुरुष तपस्वी जनों में, बहुश्रुतों में याज्ञिकों में, राजाओं में वन में वास करने वालों में एवं गुणज्ञों में भी शोभायमान होता है।

जो सन्तोषरूपी अमृत को पीकर शान्त एवं सन्तुष्ट हो जाते हैं, वे ही ज्ञानीजन आत्मा में रमण करते हुए महापद (परमात्मपद) को प्राप्त करते हैं। जो प्राप्त न होने वाली वस्तु के प्रति चिन्तित नहीं होता और प्राप्त होने वाली वस्तु के प्रति समान (हर्ष रहित) रहता है, जिसने सुख एवं दु:ख का अवलोकन नहीं किया, वास्तव में वही सन्तुष्ट कहा जाता है। जो अप्राप्त वस्तु की कभी आकांक्षा नहीं करता तथा उपलब्ध वस्तु का आवश्यकतानुसार ही उपभोग करता है, वही सौम्य एवं समभाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति सन्तुष्ट कहा जाता है।

**क्रमश: ...**

# आपदा कमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

**दयानिधि**

हर साल 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता और जीवन, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को दूर करने में हुई प्रगति को पहचानने का एक मौका है। हर साल, यह दिन दुनिया भर में उन लोगों और समुदायों को सम्मानित करने का है जो आपदाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करने और उनके सामने आने वाले खतरों को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

विनाशकारी मौसम की घटनाओं और अन्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के जवाब में आपदा लचीलापन के लिए आधिकारिक विकास सहायता के साथ-साथ क्षमता निर्माण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। यह दिन आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुरूप आपदा जोखिम और जीवन, आजीविका, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के नुकसान को रोकने और कम करने की दिशा में की जा रही प्रगति को स्वीकार करने का एक अवसर है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय

दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो लोगों और सरकारों से अपने समुदायों और देशों को अधिक आपदा-लचीला बनाने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह करता है। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की घोषणा के हिस्से के रूप में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और तबाही में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक दिन का आह्वान करने के बाद, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1989 में घोषित गया था।

2022 में, महासभा ने प्राकृतिक आपदा शमन की वैश्विक मानसिकता को बढ़ावा देने, रोकथाम और तैयारियों को कवर करने के लिए वार्षिक स्मरणोत्सव को एक उपकरण के रूप में रखने का संकल्प लिया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में 13 अक्टूबर को आधिकारिक तिथि बनाने और इसे आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का नाम बदलने का संकल्प लिया।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय को 2015 में जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विश्व सम्मेलन में सूचित किया गया था कि स्थानीय स्तर पर आपदाएं सबसे खराब होती हैं, जिसमें जबरदस्त सामाजिक और आर्थिक तबाही पैदा करने की आशंका होती है।

हर साल, अचानक आपदा के प्रकोप से लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं। विनाशकारी घटनाएं, जिनमें से कई ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ी हैं, सतत विकास निवेश और इसके वांछित परिणामों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। आपदाएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों को काफी प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से मृत्यु, घायल या विस्थापित लोगों की संख्या और प्रमुख बुनियादी ढांचे को नुकसान के मामले में इनको देखा जा सकता है।

जबकि अन्य वैश्विक समस्याएं अधिक गंभीर लग सकती हैं, यदि हम आपदा जोखिम में कमी का समाधान नहीं करते हैं तो भूख और गरीबी को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

# इजरायल पर हमास के हमले के पीछे चीन और ईरान?

**उमेश चतुर्वेदी**

सात अक्तूबर को इजरायल पर अचानक हमला भले ही हमास ने किया है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यह मानने लगा है कि यह हमला ना सिर्फ सुनियोजित है, बल्कि इसके पीछे मौजूदा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उपजी परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। हालांकि अमेरिका के हाथ अब तक ठोस सुबूत नहीं लगे है। जिस तरह हमास ने इजरायल जैसी दुर्दांत सैनिक ताकत को चौंकाया है, उसके मिसाइल रोधी आयरन डोम सिस्टम को चकमा दिया है, उससे साफ है कि उसे तकनीकी ऐसे देशों ने मुहैया करायी है, जिनकी सैनिक और वैज्ञानिक ताकत स्थापित है। शक रूस और चीन की ओर जा रहा है, जिसमें ईरान उसका मोहरा बना है।

दरअसल हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने लगा है। भारत, अमेरिका और सऊदी अरब अब ज्यादा नजदीक आ गये हैं। सऊदी अरब अपने विशाल तेल भंडार और उससे हासिल आर्थिक ताकत के दम पर अरब देशों के बीच अगुआ बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन ईरान उसकी राह में बाधा है। अमेरिकी कोशिशों से सऊदी अरब और इजरायल के बीच रिश्ते सामान्य होते जा रहे थे। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ महीनों में दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ते स्थापित होने की औपचारिक घोषणा हो सकती है, लेकिन इजरायल पर हमास के हमले और उसके बाद गाजापट्टी पर इजरायल की कार्रवाई के बाद सऊदी अरब ने इजरायल के साथ सभी संभावित रिश्तों पर रोक दिया है। वैसे सऊदी अरब और अमेरिका के

बीच नाटो जैसी संधि भी हो चुकी है। जिसमें सऊदी पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ऐसे में अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा, इससे चीन और रूस चिंतित हैं। साथ सऊदी अरब और इजरायल के बीच सामान्य राजनयिक संबंध इनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान भारत की विदेश नीति में पश्चिम एशिया को लेकर बदलाव भी आया है, जिसे मोदी सरकार ने शिखर पर पहुंचाया है। अब भारत के लिए फिलीस्तीन से ज्यादा नजदीक इजरायल है। हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए जी 20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रयासों से आईएमईसी यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कारीडोर का ऐलान हुआ। भारत ने मध्य पूर्व होते हुए बरास्ता इजरायल यूरोप तक आर्थिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे जी 20 देशों ने स्वीकार कर लिया। ध्यान रहे कि इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद नहीं थे। माना जा रहा है कि यह चीन के बीआरआई यानी बॉर्डर रोड इनिशियेटिव का जवाब है।

इस पर आगे चर्चा करने से पहले थोड़ा बीआरआई समेत चीन की साम्राज्यवादी योजना की चर्चा कर लेते हैं। चीन इस परियोजना के तहत आने वाले देशों में सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा परियोजनाओं आदि के निर्माण में निवेश कर रहा है। चीन इसके जरिए रणनीतिक रूप से ना सिर्फ वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, बल्कि बीआरआई से जुड़े देशों की आर्थिकी को नियंत्रित करता जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका इसके उदाहरण है।

हालांकि उसका दावा है कि चीनी निवेश से बीआरआई देशों का आर्थिक विकास होगा। इसी सोच के तहत चीन ने पाकिस्तान में सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कारीडोर शुरू किया था। इस परियोजना का उद्देश्य चीन के शिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़कर चीन के लिए व्यापार और परिवहन मार्ग हासिल करना है। इस परियोजना में सड़क, रेल, बिजली संयंत्र, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचा स्थापित और विकसित करना है। चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 62 अरब डॉलर का खर्च होना है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह परियोजना और इससे जुड़ी सड़क पाक अधिकृत कश्मीर से भी गुजरती है। जाहिर है कि इसी वजह से भारत इसका विरोध करता है।

विरोध स्वाभाविक भी है, इसके जरिए एक तरह से चीन भारत को घेरने की कोशिश में है। यही वजह है कि भारत इसे क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती कहता है। चीन बीआरआई और सीपीईसी के जरिए एक तरह से पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, बांग्लादेश, रूस, श्रीलंका, म्यांमार आदि को जोड़ने की तैयारी में है। इसे देख यह समझना मुश्किल नहीं है कि चीन एक तरह से भारत को सड़क और समुद्र मार्ग से घेरने की कोशिश में जुटा है। वैसे चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद का नमूना अफ्रीकी देशों और श्रीलंका में दिखने लगा है। एक तरह से चीन ने इन देशों में निवेश के बाद उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को उसने तबाह कर दिया है। चीन इन परियोजनाओं के जरिए इन देशों में अपने सैनिक अड्डे भी बनाता है। इससे भारत ही नहीं, अमेरिका की भी चिंताएं बढ़ी थीं। यही वजह है कि भारत और अमेरिका ने मिलकर आईएमईसी परियोजना को बढ़ावा दिया। अब चीन इससे चिंतित है। ईरान पर अमेरिकी दबाव लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि चीन और ईरान पर्दे के पीछे भारत और अमेरिका के खिलाफ एक होते जा रहे हैं। ईरान की दुखती रग इजरायल है, क्योंकि अमेरिका सऊदी और इजरायल के जरिए ईरान पर निगाह रखता है। सऊदी पर ईरान सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अरब देशों के बीच उसकी साख कमजोर होती है। इजरायल अरब और मुस्लिम देशों की दुखती रग है, लिहाजा इजरायल को तंग करना उसे दोहरा फायदा देता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के आईएमईसी कॉरीडोर में सहभागिता के साथ ही सऊदी अरब से बढ़ती इजरायल की दोस्ती को चुनौती देने की कोशिश में ईरान और चीन जुटे हुए हैं। एक तरफ चीन को लगता है कि भारत के प्रस्तावित आईएमईसी कॉरीडोर के चलते उसकी बीआरआई परियोजना को चुनौती मिल सकती है तो इजरायल और सऊदी दोस्ती के बाद ईरान के दबदबे पर असर पड़ता। इसीलिए दोनों ने मिलकर हमास को मदद दी और इजरायल पर हमला बोल दिया। इस बारे में एंटनी ब्लिंकन को भले ही अभी ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन इजरायल पर हमले के बाद जिस तरह ईरानी संसद में खुशियां जताईं गईं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है।

**हिन्द स्वराज्य**

# सत्याग्रह-आत्मबल (भाग-5)

**गतांक से आगे...**

अगर लोग एक बार सीख लें कि जो कानून हमें अन्यायी मालूम हो उसे मानना नामर्दगी है, तो हमें किसी का भी जुल्म बाँध नहीं सकता। यही स्वराज्य की कुंजी है। ज्यादा लोग जो कहें उसे थोड़े लोगों को मान लेना चाहिए, यह तो अनीश्वरी बात है, एक वहम है। ऐसी हजारों मिसाले मिलेंगी, जिनमें बहुतों ने जो कहा वह गलत निकला हो और थोड़े लोगों ने जो कहा वह सही निकला हो। सारे सुधार बहुत से लोगों के खिलाफ जाकर कुछ लोगों ने ही दाखिल करवाये हैं। ठगों के गाँव में अगर बहुत से लोग यह कहें कि ठग-विद्या सीखनी ही चाहिए, तो क्या कोई साधु ठग बन जायेगा? हरगिज नहीं। अन्यायी कानून को मानना चाहिए, यह वहम जब तक दूर नहीं होता तब तक हमारी गुलामी जाने वाली नहीं है। और इस वहम को सिर्फ सत्याग्रही ही दूर कर सकता है। शरीर बल का उपयोग करना, गोला-बारूद काम में लाना, हमारे सत्याग्रह के कानून के खिलाफ है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें जो पसंद है वह दूसरे आदमी से हम (जबरन) करवाना चाहते हैं। अगर यह सही हो तो फिर वह सामने वाला आदमी भी अपनी पसंद का काम हमसे करवाने के लिए हम पर गोला-बारूद चलाने का हकदार है। इस तरह तो हम कभी... एक रायपर पहुँचेंगे ही नहीं। कोल्हू के बैल की तरह आँखों पर पट्टी बाँधकर भले ही हम मान लें कि हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन दरअसल तो बैल की तरह हम गोल-गोल चक्कर ही काटते रहते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो कानून खुद को नापसन्द है उसे मानने के लिए आदमी बँधा हुआ नहीं है, उन्हें तो सत्याग्रह को ही सही साधन मानना चाहिए; वरना बड़ा विकट नतीजा आयेगा।

**क्रमश: ...**

# मोदी बनाम मुद्दे का पहला ट्रायल रन हैं ये विधानसभा चुनाव

**विनोद अग्निहोत्री**

पांच राज्यों के चुनावों की तारीखों का एलान होते ही सभी दल और नेता अपने अपने दावों वादों और इरादों के साथ मैदान में डट गए हैं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इन चुनावों को अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। हालांकि, हर चुनाव की परिस्थिति मुद्दे और मतदाताओं की मानसिकता अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव विशेषकर उत्तर भारत के तीनों राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को उन मुद्दों का ट्रायल रन जरूर माना जा सकता है, जिनको धार देकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया विशेषकर कांग्रेस लोगों के बीच जा रही है, क्योंकि अक्सर जब विपक्षी इंडिया गठबंधन से पूछा जाता है कि अगले लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उसका नेता कौन होगा, तो जवाब आता है कि वो मोदी के मुकाबले मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे।

इन चुनावों में भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, इसलिए भाजपा के महिला आरक्षण कानून और कांग्रेस के जातीय जनगणना और पिछड़ा कार्ड की पहली परीक्षा इन विधानसभा चुनावों में ही होगी। साथ ही भाजपा ने इन चुनावों में राज्यों के किसी नेता के भरोसे नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे के सहारे लड़ना तय किया है, इसलिए लोकसभा चुनावों से पहले हो रहे इन विधानसभा चुनावों में मोदी बनाम मुद्दे का यह पहला ट्रायल रन साबित हो सकता है।

इन विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस ने जातीय जनगणना का अपना कार्ड चल दिया है और राहुल गांधी लगातार जिस तरह पिछड़ों दलितों और आदिवासियों के लिए उनकी संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय करने की बात हर जनसभा में कह रहे हैं और उनकी इस बात को न सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी समेत सभी नेता हर सभा में दोहरा रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जातीय जनगणना कराने का वादा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया है और कांग्रेस कार्यसमिति ने अपना प्रस्ताव पारित करके इस पर मुहर लगा दी है। अब यह मुद्दा कांग्रेस के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। भाजपा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं के लिए संसद व विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण को मुद्दा बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी पिछड़ों के लिए अलग से कोटा तय करने की मांग जोड़ कर अपने पिछड़े कार्ड को और धार दे दी है। भाजपा जातीय जनगणना को हिंदुओं को बांटने की साजिश करार दे रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संख्या के हिसाब से हक देने की बात को अल्पसंख्यकों के हक को खत्म करने से जोड़ कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दे को लगातार धार दे रही है।

मुद्दों के अलावा इस बार जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने बिना कोई चेहरा दिए पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और लोकप्रियता पर लड़ना तय किया है, इसस ये चुनाव मोदी की लोकप्रियता की भी अग्निपरीक्षा बनते जा रहे हैं। पिछली बार भले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे जोरशोर से प्रचार किया था, लेकिन तब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ में रमन सिंह और राजस्थान में वसुधरा राजे की सरकारें थीं और उनके चेहरे भी थे। इसलिए इन राज्यों में पार्टी की हार का ठीकरा इन तीनों की विफलताओं पर फूट गया था, लेकिन इस बार सीधी तौर पर मोदी का मुकाबला कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलौत के अलावा राहुल गांधी और खरगे से भी है, क्योंकि जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ के मुकाबले मोदी का नाम लेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल के मुकाबले भाजपा मोदी को आगे रखेगी और राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलौत के मुकाबले भी भाजपा का सहारा मोदी ही होंगे। फिर कांग्रेस की तरफ खरगे राहुल और प्रियंका भी मोदी को ही निशाने पर रखेंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के छत्रपों और शीर्ष नेताओं से होगी।इसलिए इन तीनों राज्यों के नतीजों को भी मोदी की लोकप्रियता की कसौटी का पैमाना माना जाएगा।

हालांकि, 2018 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए तब उन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें थीं और ये तीनों राज्य कांग्रेस ने भाजपा से जीते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के

दलबदल की वजह से मध्य प्रदेश में भाजपा ने डेढ़ साल बाद अपनी सरकार फिर बना ली थी, इसलिए इस बार भी भाजपा के सामने वही चुनौतियां हैं जो पिछली बार थीं। यानी पहला सवाल कि क्या शिवराज सिंह चौहान पार्टी का चेहरा होंगे या नहीं।

शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान का मुकाबला पार्टी किस तरह करेगी और अगर शिवराज उसका चेहरा नहीं हैं तो फिर भाजपा का अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चेहरा कौन होगा। भाजपा ने इन चुनौतियों से मुकाबले के लिए ही एक तरफ लंबे इंतजार के बाद शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से फिर से चुनाव मैदान में उतार तो दिया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी से पहले तीन मंत्रियों एक महासचिव समेत सात सांसदों को उतारकर ये संदेश भी दे दिया कि इस बार पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई एक नाम या चेहरा नहीं दे रही है। दिग्गजों को मैदान में उतारकर पार्टी ने संगठन की गुटबाजी पर भी लगाम लगाने की कोशिश की है। करीब 18 साल से राज्य में सत्ता पर काबिज रही अपनी सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की नाराजगी को कमजोर करने के लिए भाजपा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही अपना चेहरा बना कर पार्टी के चुनाव निशान कमल को आगे कर दिया है।उम्मीदवारों की घोषणा में कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए भाजपा ने अपनी तीन सूचियां जारी कर दी हैं। उधर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक शैली के अनुरूप किसी नाम और चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में पूरा चुनाव जिस तरह लड़ा जा रहा है उससे स्पष्ट है चुनाव जीतने पर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कमलनाथ को अब राज्य में कोई चुनौती भी नहीं है, क्योंकि दूसरे बड़े नेता दिग्विजय सिंह खुद को काफी पहले मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर कर चुके हैं।इस बार कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें न के बराबर आ रही हैं, और कांग्रेस अपनी सरकार गिराए जाने को मुद्दा बनाकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है।चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के मुताबिक ग्वालियर चंबल संभाग और विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में उसे इसका लाभ मिलता भी दिख रहा है।लेकिन महाकौशल और मालवा निमाड़ क्षेत्र में उसकी भाजपा के साथ कांटे की टक्कर है जबकि भोपाल क्षेत्र में भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है।

राजस्थान में भी भाजपा 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें अभी तक वसुंधरा राजे समर्थकों को जगह नहीं मिली है। पार्टी ने यहां भी अपने कुछ सांसदों को मैदान में उतार दिया है। जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर और जयपुर राजघराने की राजकुमारी सांसद दिया कुमारी भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को चुनाव की कमान न सौंप कर भाजपा ने यहां भी सामूहिक नेतृत्व और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा राज्य में गहलौत सरकार के कामकाज, विधायकों से नाराजगी और कांग्रेस में गहलौत पायलट गुटबाजी का फायदा उठाना चाहती है। उधर अशोक गहलोत ने पिछले करीब डेढ़ साल से कई तरह की लोकलुभावन योजनाओं के जरिए लोगों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की है। सचिन पायलट से फिलहाल उनका संघर्ष विराम है। उन्हें भरोसा है कि उनकी इन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से राज्य की जनता फिर उन पर भरोसा जताएगी और कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने भले ही यहां भी यह घोषणा नहीं की है कि सरकार अगर बनी तो कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जिस तरह पूरा चुनाव अशोक गहलौत के नाम काम और चेहरे पर केंद्रित हो गया है इससे साफ है कि कांग्रेस अगर जीती तो गहलौत ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा चुनाव अभियान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम चेहरे और रणनीति के इर्द गिर्द है। राज्य के दूसरे बड़े नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार टीएस सिंहदेव बाबा को उपमुख्यमंत्री बनाकर संतुष्ट कर दिया गया है। जिस तरह पूरे पांच साल भाजपा ने यहां भूपेश सरकार के खिलाफ किसी तरह का न कोई आंदोलन किया और न ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सक्रिय रहे, उससे भाजपा शुरुआती दौर में पिछड़ती दिख रही थी, लेकिन हाल ही में उम्मीदवारों की सूची जारी करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं ने पार्टी में जान डालने का काम किया है। यहां भी भाजपा बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ रही है। यहां भी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लोकप्रियता और पार्टी निशान को लेकर सामूहिक नेतृत्व के नारे के साथ मैदान में है।कांग्रेस को अगर बघेल सरकार की किसान आदिवासी और युवा कल्याण योजनाओं के बलबूते पर जीत का भरोसा है तो भाजपा सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बना रही है।

सबसे दिलचस्प चुनाव तेलंगाना में हो रहा है। यहां जिस तरह मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (पूर्व की टीआरएस) का दबदबा है, उसे इस बार कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा ने यहां खासी सक्रियता दिखाई थी और उसके प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के आक्रामक बयानों से राज्य का माहौल गरमा गया था। लेकिन कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस की जीत ने राज्य का माहौल बदल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेंवथ रेड्डी की जन यात्राओं को मिली सफलता और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभाओं व हैदराबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद हुई रैली में सोनिया गांधी को सुनने उमड़ी भीड़ ने बीआरएस के मुकाबले कांग्रेस को ला दिया है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जनसभाएं की हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही है। मिजोरम में सत्ताधारी मिजो नेशलन फ्रंट के सामने फिलहाल कोई चुनौती नहीं दिख रही है, लेकिन मणिपुर के संकट ने पूर्वोत्तर में भाजपा की छवि को कमजोर किया है। इसका फायदा यहां कांग्रेस को मिल सकता है और उसके विधायकों की संख्या कुछ बढ़ सकती है।

## तेलंगाना का चुनावी द्वंद्व, बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा की चुनौतियां

**सुधीर सक्सेना**

तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर यानी केसी राव या कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव। पहले उनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, जिसे हाल ही में भारत राष्ट्र समिति नाम दे दिया गया है। केसीआर महत्वाकांक्षी और कद्दावर क्षेत्रीय क्षत्रप हैं। उन्होंने पार्टियां बदलीं और नई पार्टी बनाई। विधायक और सांसद रहे। वर्ष 1985 से 99 के दौरान वह लगातार चार बार विधायक चुने गए। वर्ष 2000-01 में वह डिप्टी स्पीकर रहे। फिर अप्रैल, 2001 में इस्तीफा देकर उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया। वर्ष 2004 उनके जीवन में 'टर्निंग पॉइंट' साबित हुआ। कांग्रेस से गठजोड़ के चलते उन्होंने चुनाव में दोहरी जीत हासिल की। वह सिद्दीपेट से विधानसभा और करीमनगर से लोकसभा के लिए चुने गए। केंद्र में मंत्री के तौर पर उन्होंने काफी प्रतिष्ठा अर्जित की। उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि कांग्रेस की चुनौती पर पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी यह निर्भीकता तेलंगाना के लोगों को खूब रास आई। वह दो लाख से अधिक वोटों से जीते। अब उनका संकल्प था पृथक तेलंगाना, जिसकी मांग को लेकर वह नवंबर, 2009 में आमरण अनशन पर बैठ गए। जनभावनाएं उनके साथ थीं, लिहाजा अनशन के 11वें दिन उनकी मांग मान ली गई। भारत के मानचित्र पर एक नया राज्य उभरा-तेलंगाना और वह बने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। वह दिन और आज का दिन। मुख्यमंत्री केसीआर के सामने कांग्रेस और भाजपा, दोनों असहाय हैं। केसीआर के अभेद्य दुर्ग में सेंध लगाना कठिन है। केसीआर जहां तीसरी बार जनादेश हासिल करने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, जबकि कर्नाटक का किला गंवाने के बाद भाजपा तेलंगाना के गलियारे से दक्षिण में अपनी पैठ बनाना चाहती है। भाजपा का सबसे बड़ा आसरा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और शिक्षा से जुड़ी करीब 13,500 करोड़ रुपये की विविध योजनाओं की नींव रखी। मोदी की यात्रा का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने यह कहकर मखौल उड़ाया कि प्रधानमंत्री बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) के प्रमोशन टूर पर आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने भाजपा और बीआरएस के बीच एक जुबानी जंग छेड़ दी है। मोदी ने कहा कि केसीआर ने एनडीए में शामिल होने की मंशा जाहिर की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। मोदी ने परिवारवाद और खजाने की लूट पर भी तंज किया। परिवारवाद से मोदी का आशय केसीआर के बेटे, बेटी और भतीजे के राजनीतिक वर्चस्व से था। मोदी के रहस्योद्घाटन को झूठ करार देने में केसीआर और उनके पुत्र केटीआर ने देर नहीं लगाई।

## मध्यप्रदेश में कौन होगा भाजपा का सरदार

**आनंद पवार**

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में तीन केंद्रीय मंत्रियों समेत सात सांसद और एक राष्ट्रीय महासचिव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये चारों ही मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे मुख्यमंत्री बनने की खुलकर इच्छा जता रहे हैं। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कथित तौर पर सीएम पद का दावेदार बताया जाता रहा है, लेकिन वे इन अटकलों को खारिज करते रहे हैं। बता दें, सीएम शिवराज के बयानों और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीएम फेस पर चुप्पी से अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा की सूची में बड़े नाम सामने आने के बाद ऐसी अटकलों को बल भी मिला है। अब ऐसे नेताओं के नाम सीएम की कुर्सी से जोड़े जाने लगे हैं। दावेदारों में अभी पार्टी के चार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री गोपाल भार्गव, सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं।

**नरेंद्र सिंह तोमर**-केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में प्रबल दावेदार हैं, लेकिन यह तब होगा जब वे मुरैना जिले की दिमनी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर अपना असर दिखाएंगे। संघ और पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि, उनकी कमजोर कड़ी यह है कि ग्वालियर चंबल के बाहर उनका खास जनाधार नहीं है। साथ ही पार्टी ओबीसी और जातिगत समीकरणों को साधती है तो उनको दावेदारी कमजोर पड़ सकती है।

**प्रह्लाद पटेल**- नरसिंहपुर से प्रत्याशी प्रह्लाद सिंह पटेल सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं। साथ ही संगठन और संघ के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग हैं। वरिष्ठ नेता उमा भारती का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त है। यदि पार्टी ओबीसी चेहरे पर दांव लगाती है तो उनकी लॉटरी लग सकती है।

**फग्गन सिंह कुलस्ते**- मंडला जिले के निवास से प्रत्याशी

से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता है। भाजपा आदिवासी वोटों पर फोकस कर रही है। पिछले दो सालों के पार्टी के कार्यक्रम को देखें तो सबसे ज्यादा आदिवासी महापुरुषों पर केंद्रित रहा है। ऐसे में पार्टी यहां आदिवासी कार्ड को भुनाने में लगी है। साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते के चेहरे पर दांव उसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी की उम्मीदों पर कुलस्ते खरे उतरते हैं तो उनकी किस्मत पलट सकती है।

**कैलाश विजयवर्गीय**- भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर-1 से प्रत्याशी हैं और भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जड़ें मजबूत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही एमपी में पार्टी के नाराज वरिष्ठों को मनाने में उनका रोल रहा है। प्रदेश की राजनीति से दूर रहे कैलाश की वापसी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में हुई है। संगठन के आला नेताओं के करीबी और भरोसेमंद हैं। अपने कद और भविष्य को लेकर अभी से कैलाश इशारा करने लगे हैं। ऐसे में उन्हें भी सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

**शिवराज सिंह चौहान**- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपी में करीब 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। इनके चेहरे का तोड़ आज भी भाजपा के पास नहीं है। साथ ही सरल स्वभाव की वजह से उनकी अपनी अलग पहचान है। अब तक वे पार्टी के सर्वमान्य चेहरा रहे हैं, लेकिन कथित तौर पर पार्टी उनसे छुटकारा चाह रही है। इसके संकेत मिलने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी अब खुद ही लोगों से पूछ रहे हैं कि मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या बुरी? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं?

**ज्योतिरादित्य सिंधिया**- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा ने सत्ता में वापसी की। सिंधिया कुछ ही दिनों में संगठन के करीब पहुंच गए। मोदी कैबिनेट में भी वे अच्छी पोजिशन पर हैं। उनकी देश में अलग पहचान है। हालांकि, उनकी कमजोरी यह है कि उनके आने के बाद भाजपा उनके इलाके में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर की दो सीटें हार गईं।

**वीडी शर्मा**- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं। बेदाग और स्वच्छ छवि के शर्मा संघ के करीबी हैं। ब्राह्मण चेहरा हैं। युवाओं और कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं। हालांकि, पार्टी ने पिछले तीन मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से दिए हैं। पार्टी के जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने से शर्मा की दावेदारी कमजोर हो सकती है।

**गोपाल भार्गव**- शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे 2013 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले 15 साल से मंत्री के पद पर काबिज हैं। भार्गव की छवि बेदाग है। सागर में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इशारों-इशारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु आज्ञा हुई है कि एक चुनाव और लड़ना है। हालांकि, ब्राह्मण नेता होने के चलते पार्टी यदि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधती है तो उनका दावा कमजोर पड़ सकता है।

**सुमेर सिंह सोलंकी**- सुमेर सिंह सोलंकी बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर से राज्यसभा सांसद बने। उनकी संघ और संगठन दोनों में मजबूत पकड़ है। सुमेर सिंह खरगोन-बड़वानी के पूर्व भाजपा सांसद माकन सिंह सोलंकी के भतीजे हैं। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हैं। अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर काफी सक्रिय हैं और बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। भाजपा ऐसे की नेताओं को आगे बढ़ाकर चौंकाते आई है।

**नरोत्तम मिश्रा**- प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में नंबर दो पर बताई जाती है। प्रदेश में बड़े ब्राह्मण नेता है। 2018 में भाजपा चुनाव हार गई थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थित विधायकों को भाजपा में शामिल कराने ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, जिसकी सफलता में नरोत्तम मिश्रा ने अहम रोल निभाया था।

## क्या चुनावी रेवड़ियां बनेंगी सत्ता में वापसी की चाभी?

**विनोद पाठक**

लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जाने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान हो गया है। हिंदी पट्टी के राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होना है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साढ़े नौ साल से केंद्र की सत्ता में रहने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा। यह चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों में सरकारों ने लोक लुभावन घोषणाएं करने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन चुनावों में फ्रीबीज या चुनावी रेवड़ियों की भी परीक्षा होने वाली है। विपक्ष के जातीय जनगणना के दांव पर जनता का रुख भी इन चुनावों में पता चलने वाला है।

राज्यवार बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले पांच साल से अपनी कुर्सी को बचाते आ रहे हैं। पांच साल में कई ऐसे अवसर आए, जब लगा कि गहलोत की सरकार गिर जाएगी। वर्ष 2020 में ठीक कोरोना के बीच कांग्रेस में बगावत हो गई थी। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की सूझबूझ से सरकार बच तो गई, लेकिन मुख्यमंत्री निर्दलीय विधायकों पर आश्रित होकर रह गए। उसी का नतीजा था कि मुख्यमंत्री गर्वनेंस से ज्यादा विधायकों को खुश करने में जुटे रहे। चुनाव से ठीक छह महीने पहले गहलोत ने लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी। बिजली बिल माफी से लेकर मुफ्त मोबाइल बांटने तक शायद ही कोई सेक्टर होगा, जिसके लिए गहलोत ने घोषणा न की हो। 33 से बढ़ाकर 53 जिले तक कर दिए गए। जाति के आधार पर बोर्ड बना दिए गए। गहलोत जहां अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपरलीक, तुष्टिकरण जैसे मुद्दों को आधार बना रही है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई में आपसी प्रतिद्वंद्वता के चलते चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है।

रोचक बात यह है कि राजस्थान से कांग्रेस का गांधी परिवार नदारद है। चुनाव गहलोत बनाम मोदी का बन गया है। पिछली बार कांग्रेस को सत्ता तक लाने वाले सचिन पायलट मौन हैं तो भाजपा की स्टार नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है। राजस्थान में पिछले तीन दशक से हर पांच साल पर सत्ता बदलती आ रही है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि रिवाज बदलेगा या नहीं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से चंद सीटें कम रह गई थीं। कांग्रेस ने युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह अनुभवी कमलनाथ को सत्ता की बागडोर सौंप दी थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते भारतीय जनता पार्टी पुन: सत्ता में आई।

शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के कयास चलते रहे। अभी भले चुनाव शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ा जा रहा है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती है तो उन्हीं को कुर्सी मिलेगी, इसका कोई स्पष्ट संकेत पार्टी की ओर से नजर नहीं आ रहा है। इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कद्दावर कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को टिकट दिया है तो उससे भी शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी बढ़ी है। हालांकि, चौहान भी फ्रीबीज के सहारे सत्ता वापसी की

चाभी ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस में मुख्य चेहरा कमलनाथ का ही नजर आ रहा है। वह अपने एक साल के कार्यकाल को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले कुछ दिनों में प्रियंका के कई दौरे हुए हैं। सत्ता विरोधी लहर के बीच भाजपा के लिए सत्ता में वापसी उतनी आसान नहीं है, लेकिन कमजोर कांग्रेस किस तरह टक्कर दे पाएगी, यह चुनाव नतीजों से पता चलेगा।

छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद वर्ष 2018 में कांग्रेस को सत्ता हासिल हुई थी। भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहद अच्छी स्थिति में है। हालांकि, राज्य में भूपेश बघेल और टी.एस.सिंह देव में कुछ वैसी ही नोकझोंक चलती रही, जैसी राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रही थी।

भूपेश बघेल आलाकमान को साधकर कुर्सी बचाने में सफल तो हुए। सत्ता में पुन: वापसी के लिए भूपेश बघेल ने भी चुनावी रेवड़ियों का सहारा लिया है। अब तक बघेल काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पिछले पांच साल ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। यही कारण है कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में के.चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति सत्ता में है। राव दो बार से सत्ता में बने हुए हैं। जिस तरह से वर्ष 2018 में उन्हें बहुमत मिला था तो कहा जा सकता है कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफी ऊंचा है। हालांकि, राव भी सरकार विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। उन्हें कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया तो लग रहा है कि वो यहां तीसरी ताकत बन रही है। के. चंद्रशेखर राव ने भी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, जहां उन्होंने मुफ्त की घोषणाएं न की हों। खासकर अल्पसंख्यकों को लेकर उनकी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर लिया। तेलंगाना में निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। चंद्रशेखर राव की बीआरएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक-दूसरे से मुकाबला करते नजर आएंगे। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और उसने वर्ष 2018 में 40 सीटों वाली विधानसभा में 26 सीटें जीती थीं। यहां पर मुख्य रूप से मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपुल्स मूवमेंट के बीच है। राष्ट्रीय पार्टियों यहां अपनी जमीन नहीं तैयार कर सकी हैं।

जहां तक तीसरे मोर्चे या अन्य दलों की बात है तो वो अभी कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कुछ महीने पहले जोर-शोर से प्रचार किया था, लेकिन उसके प्रचार की गति धीमी पड़ चुकी है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ सीटों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, वह भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला कर पाएगी, यह मुश्किल लगता है। भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। कुछ-कुछ यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी की भी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगते इलाकों में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है। इन चुनावों में नवगठित इंडिया गठबंधन का भी टेस्ट होना बाकी है। यह देखना होगा कि लोकसभा से पांच महीने पहले हो रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में यह गठबंधन एकजुट रहता है या नहीं। यदि आपसी प्रतिद्वंद्वता को छोड़कर इंडिया गठबंधन के दल पांचों राज्यों में एकजुट हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को वर्ष 2024 में बड़ी चुनौती दे सकते हैं।

# कान के पर्दे खराब करेगा ईयरफोन : दिमाग पर भी असर; कितने घंटे यूज करना है सेफ

**ईयर फोन या** ईयर बड्स। पिछले कुछ सालों में इसका इस्तेमाल बढ़ा है। छोटे-छोटे बच्चे के लेकर बुजुर्ग सब इसे यूज कर रहे हैं।

किसी को कॉल करनी हो, मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेज लेनी हो, म्यूजिक सुनना हो, ओटीटी सीरीज को बिंज वॉच करना हो, तो घंटों तक कान में ईयरफोन लगा रहता है। सड़क पर देखें तो ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए लोग बेखौफ ईयरफोन लगाकर ड्राइव और वॉक कर रहे हैं। प्राइवेसी के लिहाज से जिसे लोग अच्छा मान रहे हैं, उसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। हेडफोन या ईयरफोन से आने वाली आवाज आपके ईयरड्रम को भारी नुकसान पहुंचा रही है। किस हद तक इससे कानों को नुकसान होगा, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए।

'ईयर फोन और ईयर बड्स के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान पर पिछले कई सालों से रिसर्च हो रही है। हर हफ्ते, हमारे सामने कान के इन्फेक्शन के चार मामले सामने आते हैं, जिसमें ईयरफोन का लंबे समय तक यूज करना आम बात है। वातावरण में नमी के कारण गर्म और उमस भरे मौसम में संक्रमण अधिक बढ़ जाता है।

### अब एक डेटा पर नजर डालें, नीचे लगी क्रिएटिव में...

डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि रेगुलर ईयरफोन यूज करने से 2050 तक 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के कान खराब हो जाएंगे। वाइब्रेशन ज्यादा होने से सुनने वाले सेल्स अपनी संवेदनशीलता खो देते हैं। जिससे बहरापन हो जाता है। इसके साथ कई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जैसे-

कान में दर्द: देर तक रेगुलर यूज करने से कानों में दर्द शुरु हो सकता है। कई बार ये दर्द तेज भी हो सकता है जिससे कानों में भारीपन होने की संभावना बढ़ जाती है।

बहरापन: ज्यादा देर तक लगाने और वाइब्रेशन से कानों की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे नसों में सूजन आ सकती है। सेंसिटिविटी खोने से बहरापन भी हो सकता है।

सिरदर्द: डेली तेज आवाज में सुनने से कानों को बल्कि दिमाग को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तेज वाइब्रेशन से हमें सिरदर्द और नींद न आने की परेशानी होने लगती है।

कान सुन्न होना: लंबे समय तक सुनने पर कान सुन्न हो सकते हैं। मानसिक समस्याएं जैसे चक्कर आना, नींद न आने की प्रॉब्लम होने लगती है।

सुनने की क्षमता प्रभावित: धीरे-धीरे सुनने की क्षमता कम होने लगती है और इंफेक्शन भी हो सकता है। इससे टिनिटस मतलब कान में गुंजन या अतिरिक्त ध्वनि सुनाई देती है।

नोट: कान में अक्सर सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है या लेटने पर चक्कर आते हों तो बिना देर किए ईएनटी स्पेशलिस्ट से सलाह लें।

जो लोग ईयरबड्स और हेडफोन का लगातार कई-कई घंटों तक यूज करते हैं, रात में लगाकर सो जाते हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कान के अंदर एक पर्दा मौजूद होता है जिसे ईयरड्रम कहते हैं। इसमें तमाम नसें और अंग होते हैं, जो दिमाग से कनेक्ट होते हैं। जब ईयरफोन या हेडफोन लगाकर तेज आवाज में सुनते हैं, तो आवाज और उसका वाइब्रेशन दवाब के साथ ईयर ड्रम से टकराता है जिससे समस्याएं पैदा होती हैं। एक बार जब यह समस्या हो जाती है तो परमानेंट बन जाती है। अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए, तो यह डेंजरस भी हो सकती है। ईयरफोन के मुकाबले हेडफोन थोड़ा सुरक्षित है। ईयरफोन कान के अंदर लगता है इसलिए वाईब्रेशन की कान के पर्दे से दूरी कम होती है जबकि हेडफोन कान के बाहर लगता है जिससे पर्दे से दूरी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यह कम नुकसान करता है। लेकिन दोनों का यूज ज्यादा किया जाए और तेज आवाज में सुना जाए, तो नुकसान ही पहुंचाएंगे।

डॉक्टर का मानना है कि दिन में सिर्फ 30 मिनट ही ईयरफोन का यूज करना चाहिए। इसके अलावा जब जरूरत हो तब करें। सबसे पहली बात तो ईयरफोन का यूज जरूरत पड़ने पर ही करें। बाकी बातें नीचे लगे क्रिएटिव से समझते हैं।

# ऑनलाइन महीने का राशन खरीदते वक्त रखें इन बातों का ध्यान, ऐसे बचा सकते हैं हजारों रुपये

महीने का राशन खरीदने के दौरान, कई बार हम अपने बजट से भी ज्यादा सामान ऑर्डर कर देते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम बिना इस्तेमाल के भी कई सामान ऑर्डर कर देते हैं। ऑनलाइन माध्यम से खरीदारी करते वक्त हम ऑफर की लालच में भी आ कर के शॉपिंग कर लेते हैं। जिसका असर हमारे जेब पर पड़ता है। इसलिए, महीने का राशन खरीदते वक्त इन बातों का ध्यान रखना बेहतर हो सकता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदें, जो इस्तेमाल का भी हो और आपको समय और पैसों की बचत मिल सके।

अगर आप किसी ऑनलाइन राशन की वेबसाइट या ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो जरूर तय करें कि यह आपकी जरूरतों के अनुसार प्राथमिकता देता है और आपके इलाके में इसकी सेवा उपलब्ध है।

जब आप राशन खरीदने के लिए ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तो जान लें कि आपका लेनदेन सुरक्षित माध्यम से हो रहा है। आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी भी असुरक्षित स्थान पर दर्ज न करें।

राशन उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। ऑनलाइन खरीदी गई चीजों का लेबल और गुणवत्ता सत्यापन करें और अगर आपको कोई असुविधा मिलती है, तो कस्टमर केयर को उसकी कंप्लेंट करें।

राशन की डिलीवरी की विशेषता को ध्यान में रखें। डिलीवरी समय

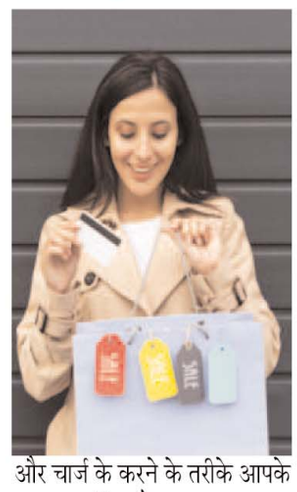

और चार्ज के करने के तरीके आपके अनुसार उचित है।

अगर कोई समस्या या शिकायत होती है, तो आपको खरीदारी करने वाली वेबसाइट या ऐप के सहायता केंद्र से संपर्क करने के लिए उनकी संपर्क जानकारी होनी चाहिए।

### ऑनलाइन महीने का राशन खरीदते समय इन बातों का पालन करें

### जरूरी सामान का लिस्ट बना लें

सबसे पहले, अपनी जरूरतों का आकलन करें और यह तय करें कि आपको कितना राशन चाहिए। अपने परिवार के आकार, आहार की आदतों और रसोई की आदतों पर विचार कर के आप लिस्ट बना सकते हैं। यह अच्छा तरीका हो सकता है कि आप पहले से ही अपना बजट बना लें, ताकि जरूरी सामान लिया जा सके।

### वेबसाइटों की तुलना करें

एक बार जब आप अपनी जरूरतों को समझ लें, तो कई अलग-अलग वेबसाइटों की तुलना करें। विभिन्न वेबसाइटों पर कीमतें और उत्पादों की उपलब्धता में काफी अंतर हो सकता है। वही सामान कार्ट में डालें जिसका दाम आपके अनुसार हो। इससे आप फिजूल खर्च से बच सकते हैं।

### अधिक ऑफर के लालच से बचें

कई वेबसाइटें छूट और ऑफर प्रदान करती हैं। इन ऑफर का सही लाभ उठाकर आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान इसलिए न खरीद लें क्योंकि आपको यह उत्पाद अधिक ऑफर में मिल रहा है। अधिक ऑफर वाले सामान

जिनकी जरूरत नहीं है, इसे खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं।

### फैंसी आइटम के बजाए किफायती सामान खरीदने की कोशिश करें

अगर आप एक बड़ी मात्रा में राशन खरीद रहे हैं, तो मुफ्त डिलीवरी के लिए योग्य बनने की कोशिश करें। यह आपको पैसे बचाने में मदद करेगा। साथ ही कोशिश करें अपने राशन में वही समान लें जो किफायती और पूरक है। फैंसी समान आपके बजट लेवल को बढ़ा सकती है। ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

### रिटर्न पॉलिसी के बारे में जरूर चेक कर लें

अगर आप किसी उत्पाद से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी एक अच्छी रिटर्न पॉलिसी प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में आपको अधिक समय न लगे। निर्धारित समय सीमा के अंदर ही आपका सामान रिटर्न हो सके।

ऑनलाइन महीने का राशन खरीदना एक आसान और सुविधाजनक तरीका है। इन तरीकों का पालन करके, आप पैसे बचा सकते हैं और अपने परिवार के लिए स्वस्थ और पौष्टिक राशन खरीद सकते हैं। इससे आपको पैसे बचाने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सकता है।

# बढ़िया हनीमून के लिए लक्षद्वीप का ये आईलैंड मालदीव से कम नहीं

हनीमून मनाने के विदेश में नहीं, बल्कि भारत के लक्षद्वीप में मौजूद इन हसीन आइलैंड के किनारे पहुंच सकते हैं। इन द्वीपों की खूबसूरती दुनिया भर में फेमस हैं। लक्षद्वीप भारत का एक बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि यहां सिर्फ देशी ही नहीं, बल्कि विदेशी सैलानी भी घूमने के लिए पहुंचते हैं।

लक्षद्वीप की खूबसूरती में चार चांद लगाने काम करते हैं यहां मौजूद आइलैंड यानी द्वीप। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप एक नहीं बल्कि, दर्जन से भी अधिक हसीन द्वीपों के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप में स्थित कुछ आइलैंड की खूबसूरती और मेहमान नवाजी इस कदर प्रचलित है कि यहां हर रोज दर्जन से भी अधिक कपल्स हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे हसीन आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप भी हसीन हनीमून मनाने के लिए पहुंच सकते हैं।

## मिनिकॉय द्वीप

लक्षद्वीप में स्थित सबसे खूबसूरत आइलैंड की बात होती है, तो सबसे पहले मिनिकॉय द्वीप का जिक्र जरूर होता है। यह आइलैंड जिस तरह अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, ठीक उसी तरह कपल्स के बीच भी फेमस है।

बेहतरीन नजारे और हसीन मेहमान नवाजी के लिए चलते हर दिन दर्जन से अधिक कपल्स यहां हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं। मिनिकॉय द्वीप में मौजूद आलीशान और हसीन रिसॉर्ट भी कपल्स की स्वागत में खड़े रहते हैं। यहां स्थित रिसॉर्ट द्वारा कपल्स को एक से एक बेहतरीन चीजों की सुविधा दी जाती है।

## अगत्ती द्वीप

लक्षद्वीप में मौजूद किसी हसीन और मनमोहक द्वीपों पर घूमने और हनीमून मनाने की बात होती है, तो अगत्ती द्वीप का नाम जरूर लिया जाता है। इसलिए अगत्ती द्वीप को हनीमून का स्वर्ग भी माना जाता है।

अरब सागर के नीले पानी, सफेद रेत और बड़े-बड़े पेड़ अगत्ती द्वीप की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। समुद्र किनारे मौजूद टेंट और टेंट के पास जलती रंगीन लाइट्स और साथ में हमसफर के साथ हनीमून मानना किसी हसीन जन्नत से कम नहीं। अगत्ती द्वीप में हनीमून मनाने के अलावा यहां आप वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

## बांगरम द्वीप

हिंद महासागर के साफ और नीले पानी में स्थित बांगरम द्वीप देशी और विदेशी सैलानियों के बीच काफी फेमस आइलैंड माना जाता है। मूंगा चट्टान और लुभावने दृश्यों के लिए फेमस बांगरम द्वीप कपल्स के बीच भी काफी लोकप्रिय है।

बांगरम द्वीप के आसपास मौजूद रिसॉर्ट कपल्स के लिए एक से एक बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करती है। कई रिसॉर्ट रात के समय कपल्स के लिए हसीन लाइट्स और डिनर की भी सुविधा प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि बांगरम द्वीप का सूर्योदय और सूर्यास्त अन्य आइलैंड से काफी फेमस माना जाता है। (मालदीव की तरह खूबसूरत है भारत का यह आइलैंड)

## कावारत्ती द्वीप

लक्षद्वीप की राजधानी होने के लिए कावारत्ती द्वीप अन्य पर्यटकों के साथ-साथ कपल्स के बीच भी काफी फेमस माना जाता है। कावारत्ती द्वीप सबसे सुंदर रत्नों में से एक माना जाता है। कावारत्ती द्वीप नीले पानी, सफेद रेत और हसीन नजारों के लिए बहुत फेमस है। समुद्र के बीच में मौजूद यहां के रिसॉर्ट कपल्स को एक से एक हसीन चीजों की सुविधा देते हैं। कई रिसॉर्ट और होटल कपल्स के लिए दुल्हन की तरह सजा देते हैं। यहां पार्टनर के साथ वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाते हुए यादगार हनीमून मना सकते हैं। यहां स्कूबा डाइविंग करना न भूलें।

# कम समय में ऐसे करें पूरे घर की सफाई

घर में मेहमान आने वाले हैं और आपके पास काफ़ी कम समय रह गया है तो ऐसे करे अपने घर की सफ़ाई मिनटों में। आज हम आपको कुछ आसान हैक्स बताने वाले हैं।

कई बार घर में मेहमान अचानक आने वाले होते हैं और हमें कुछ समय पहले ही पता चलता है। इस समय समझ नहीं आता कि घर की सफ़ाई किस कोने से करना शुरू करें। अगर आप भी अपने घर को मिनटों में चमकाना चाहती है तो आज हम आपको कुछ आसान हैक्स के बारे में बताने वाले हैं। जिनकी मदद से आप अपने घर को मिनटों में चमका सकते हैं।

### लिविंग रूम की करें सफ़ाई

ऐसे समय में आपको सबसे पहले अपनी लिविंग रूम की सफ़ाई करनी चाहिए जहाँ आपके मेहमान आ के बैठने वाले हैं।

सबसे पहले आपको बिखरे हुए सामानों को एक जगह इकट्ठा करना है और उन्हें सही स्थान पर रख देना है। इसके बाद आपको अपने घर में तुरंत झाड़ू पोंछा लगाना हैं।

### सोफ़ा रखे साफ

अगर आपका सोफ़ा गंदा है तो आपको तुरंत इसकी डस्टिन शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आपको क़रीबन पाँच मिनट का समय लगेगा। सोफ़ा साफ़ करना काफ़ी आसान है हालाँकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसके ऊपर कवर भी लगा सकते हैं। तो आप अपना काफ़ी समय बचा सकती है।

### आपस में मिलकर करे काम

घर की सफ़ाई तुरंत करने के लिए आपको किसी और की सहायता लेनी होगी ऐसे में कोशिश करें कि सभी लोग मिल के सफ़ाई करें। मिनटों में सफ़ाई करने के लिए आपको अपने घर के सभी बेडशीट को चेंज कर देना चाहिए। बेडशीट सईद से लगाते और किचन का बिखरा हुआ सारा सामान एक जगह समेटकर रखते दें।

# घर के पूजा रूम का ऐसे करें मेकओवर, दिखेगा बहुत सुंदर

कुछ ही दिनों में फेस्टिवल सीजन आने वाला है और ऐसे में आप अलग-अलग तरह से पूजा घर का मेकओवर कर सकती हैं। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपको अधिक खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और मंदिर बहुत अधिक सुंदर भी लगेगा। आप चाहें तो मंदिर को अलग तरह से पेंट कर सकती हैं या फिर पूजा रूम के कलर को चेंज कर सकती हैं।

### पूजा घर में लगाएं लाइट्स

अलग-अलग डिजाइन के दीए और लाइट्स से भी पूजा घर को शानादर तरह से न्यू लुक दे सकती हैं। ध्यान रखें कि दब भी मंदिर में बड़े दीए रखें तो उन्हें पर्दों के आसपास न रखें। इसके अलावा आपको पूजा घर में फेयरी लाइट्स भी लगानी चाहिए। इन लाइट्स से मंदिर बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा आप छोटी-छोटी वॉटर कैंडल्स भी रख सकती हैं।

### पूजा घर में लगाएं वॉलपेपर्स

आप पूजा घर में मंदिर के साइड में खाली स्पेस पर वॉलपेपर्स भी लगा सकती हैं। इसके अलावा आप मार्केट से जाली पैनल खरीदकर मंदिर के आगे वाले भाग को कवर करने के लिए लगा सकती हैं। इससे मंदिर कवर भी हो जाएगा और यह दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। आप मंदिरों के लिए लकड़ी के पैनलिंग का उपयोग कर सकती हैं। पैनल के लिए लकड़ी का उपयोग करने से आपके पैसे भी बचेंगे और मंदिर की सुंदरता भी बढ़ेगी।

### रंगीन लकड़ियों से सजाएं मंदिर का बैकग्राउंड

आप कलरफुल लकड़कियों की मदद से भी पूजा घर को न्यू लुक दे सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ लकड़ियां लेनी होंगी जो सेम साइज में हो और फिर उन्हें कलर करना होगा जो मंदिर से मैच करें। इसके बाद रंगीन लकड़ियों से आप मंदिर के बैकग्राउंड को खास डिजाइन में सजा सकती हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

## दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर तक पी-20 शिखर सम्मेलन

**नईदिल्ली।** दिल्ली में पी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 25 से अधिक देशों के वक्ता और संसदीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस ने द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले एक यातायात सलाह जारी की है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शुक्रवार को मेट्रो ट्रेन के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक जाने की संभावना है। हालांकि, सुरक्षा कारणों से उन्होंने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। एक वरिष्ठ यातायात अधिकारी ने बताया, लगभग 27 देशों से, वहां की संसद के स्पीकर और संसदीय प्रतिनिधि पी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इन तीन दिनों तक अकबर रोड, सरदार पटेल मार्ग से धौला कुआं फ्लाईओवर, हवाई अड्डे के पास स्थित मेहराम नगर क्षेत्र, पालम फ्लाईओवर और दुलसिरस चौक पर सुबह सात बजे से रात दस बजे के बीच यातायात को नियंत्रित किया जाएगा।

## गंगाजल पर 18% जीएसटी लूट और पाखंड की पराकाष्ठा: खड़गे

**नई दिल्ली।** कांग्रेस ने गंगाजल पर कथित तौर पर 18 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के लिए गुरुवार को को मोदी सरकार की आलोचना की और इसे लूट और पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार के उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे के बीच कांग्रेस ने यह भी सवाल किया कि वह हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा कब करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्विटर (अब एक्स) पर एक पोस्ट में कहा, मोदी जी, मोक्ष प्रदाता मां गंगा का महत्व एक आम भारतीय के लिए जन्म से लेकर जीवन के अंत तक बहुत अधिक है। यह अच्छा है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, लेकिन आपकी सरकार ने पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। उन्होंने कहा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जो अपने घरों में गंगाजल रखने इसे ऑर्डर देकर मंगाते हैं। यह आपकी सरकार की लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है।

## नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन माह के लिए बढ़ी

**नईदिल्ली।** उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को बृहस्पतिवार को तीन माह के लिए बढ़ा दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई को अपने आदेश में मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मलिक ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। धन शोधन के इस मामले की जांच ईडी कर रहा है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दिये जाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस वी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं किया। ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।

## अगर हम भ्रष्टाचारी है, तो हमारे साथ चर्चा क्यों : सुप्रिया सुले

**मुंबई।** महाराष्ट्र के शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने भ्रष्टाचार मामले में भाजपा से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि राकांपा पार्टी के भ्रष्ट होने के बावजूद भाजपा पार्टी ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने भाजपा द्वारा पार्टी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को दोहरा चेहरा करार दिया है। उन्होंने कहा, मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि एक तरफ आप हमें भ्रष्टाचार पार्टी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ छगन भुजबल कहते हैं कि राकांपा और भाजपा के बीच बात चल रही थी। जब राकांपा भष्टाचारी है तो भाजपा हमसे क्यों बात की थी? उन्होंने पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए कहा, इससे साफ पता चलता है कि भाजपा हम पर गलत आरोप लगा रही है। एक तरफ वे हमें भ्रष्टाचारी बुलाते हैं और दूसरी तरफ वही हमसे चर्चा करने आते हैं। इससे भाजपा का दोहरा चेहरा स्पष्ट होता है।

## 2024 में केंद्र में नहीं होगी भाजपा की सरकार : राउत

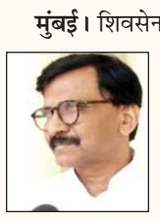

**मुंबई।** शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भविष्य की राजनीति को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। संजय राउत ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे और न ही तीसरी बार देश कमान उनके हाथ में आने जा रही है। सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से कहा, विपक्षी दलों ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया अलायंस का गठन किया गया है। इस कारण से इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले दल 2024 के चुनावों पर ही ज्यादा चर्चा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं एक बात तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। 2024 में न तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और न तो केंद्र की सत्ता में भाजपा होगी।

### प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को दिया 4200 करोड़ का तोहफा

# चुनौतियों से घिरी दुनिया में आज भारत की आवाज बुलंद : मोदी

**पिथौरागढ़।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। पिथौरागढ़ में उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी यहां, 4 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश ने लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। दशकों से लंबित ये काम आपका भाई और आपका बेटा कर पाया है। उस समय में भी यहां की बहनों ने बहुत सारी चिट्ठियां भेजीं।

मोदी ने कहा कि चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद होती जा रही है। अभी कुछ सप्ताह पहले ही जी20 का इतना बड़ा शानदार आयोजन हुआ, उसमें भी दुनिया ने हम भारतीयों का लोहा माना है। उन्होंने कहा कि दूर-सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने-कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए, सिर्फ 5 वर्षों में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये 13.5 करोड़ लोग, इस बात का उदाहरण हैं कि भारत अपनी गरीबी मिटा सकता है। मोदी ने कहा कि पहले नारा दिया जाता था कि गरीबी हटाओ, मोदी कह रहा है? कि हम मिलकर गरीबी हटाकर रहेंगे। हम जिम्मेदारी लेते हैं और जी-जान से जुट जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर क्षेत्र, हर मैदान में हमारा तिरंगा ऊंचे से ऊंचा लहरा रहा है। हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। जिस जगह पर चंद्रयान से लैंडिंग की है, भारत ने उस स्थान को शिव-शक्ति का नाम दिया है। उन्होंने कहा

कि स्पेस में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी भारत का दम आज दुनिया देख रही है। हाल में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। वन रैंक-वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया है।

मोदी ने कहा कि हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं, बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है।वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये काम पहले की सरकारों द्वारा भी किया जा सकता था। लेकिन पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। आज का नया भारत, पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और उत्तराखंड के सारे सपने व संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है।

### जवानों का समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणा : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान पार्वती कुंड और गुंजी में भारतीय सेना, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनकी अटूट सेवा वास्तव में सराहनीय है। उनकी भावना और समर्पण पूरे देश को प्रेरित करता है। इससे पहले दिन में, प्रधान मंत्री ने राज्य में लगभग 4,200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अधिकारियों के अनुसार, परियोजनाओं से पहाड़ी राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, खेल, पर्यटन, आपदा शमन और बागवानी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड दौरे को लेकर मोदी ने कहा कि यहां मानसखंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैंची धाम, कटारमल, नैनादेवी, नानकमत्ता, रीठासाहिब जैसे अनेकों देव स्थलों की श्रृखंला का वैभव विद्यमान हैं। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थभूमि पर आकर मैं धन्य हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और उत्तराखंड के सारे सपने व संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। हमें केदारखंड के साथ साथ मानसखंड को भी उस ऊंचाई तक ले जाना है। हम केदारखंड और मानसखंड की कनेक्टिविटी पर भी जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे लोग जोगेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सकें, ये प्रयास किया जा रहा है।

# 4 नवंबर को नागपुर में हो सकती है 'इंडिया' की बैठक

### राहुल, मल्लिकार्जुन व शरद पवार ने ममता से की फोन पर चर्चा

**नईदिल्ली।** एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को लेकर बनी इंडिया गठबंधन की अगली बैठक नवंबर की शुरुआत में होने की संभावना है। इस संबंध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और एनसीपी नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ फोन पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक हाल में विदेश दौरे में चोट लगने के कारण डॉक्टरों की सलाह पर फिलहाल कालीघाट स्थित अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ कर रहीं ममता बनर्जी से तीनों विपक्षी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी हालचाल जाना।

#### तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया प्रस्ताव

तृणमूल नेताओं के अनुसार, इसके बाद इंडिया गठबंधन की अगली बैठक पर चर्चा की गयी। इसमें कांग्रेस और राकांपा नेता इस महीने के ही अंत में नागपुर में बैठक के पक्ष में हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि उस समय लक्ष्मी पूजा के कारण उनका जाना संभव नहीं होगा। ममता ने सुझाव दिया कि अगर चार-पांच नवंबर तक बैठक होती है, तो वह जा सकती हैं।जानकारी के अनुसार, ममता बनर्जी के सुझाव पर तीनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक चार-पांच नवंबर को नागपुर में होगी और ममता बनर्जी उसमें शामिल होंगी।

#### नागपुर के अलावा लखनऊ, कोलकाता और दिल्ली में भी अगली बैठक को लेकर चर्चा

नागपुर के अलावा लखनऊ, कोलकाता और दिल्ली में भी अगली बैठक को लेकर चर्चा है। हालांकि पिछले महीने 13 सितंबर को विपक्षी दलों के समन्वय समिति की बैठक में जिन पांच शहरों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, उसमें नागपुर फाइनल हुआ था। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन की इससे पहले तीन बैठकें हो चुकी है। पटना, मुंबई व बेंगलुरु में होने वालीं तीनों बैठकों में ममता हिस्सा ले चुकी हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन में सीट समझौते को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है।

#### विभिन्न राज्यों में सीट समझौते में बंगाल एक बड़ा कांटा

सहयोगी दलों को अहसास हो रहा है कि विभिन्न राज्यों में सीट समझौते में बंगाल एक बड़ा कांटा है। हाल में एनसीपी नेता शरद पवार ने खुलेआम कहा था कि विधानसभा चुनाव में बंगाल में कांग्रेस, तृणमूल व वामदल भले एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। हालांकि पवार के इस बयान पर बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष व वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी व माकपा नेताओं ने आपत्ति जतायी थी। दरअसल, ममता के घुर विरोधी माने जानेवाले अधीर व माकपा नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के बावजूद बंगाल में ममता के साथ मिलकर किसी हाल में लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में यहां सीट समझौते की राह आसान नहीं दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जातीय गणना के मुद्दे पर भी तृणमूल को मनाने के लिए बात करना चाहती है। हालांकि तृणमूल नेतृत्व ने इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साध रखी है।

खेल
प्रमुख समाचार

## चेपॉक पर न्यूजीलैंड का मुकाबला बांग्लादेश से आज

**नईदिल्ली।** आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 11वें मैच में 13 अक्टूबर को दोपहर 2.00 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम उर्फ चेपॉक में न्यूजीलैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इंग्लैंड और नीदरलैंड्स को हराने के बाद कीवी टीम प्रबल दावेदार के रूप में मुकाबले में उतरेगी।

अफगानिस्तान के खिलाफ छह विकेट की आसान जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाला बांग्लादेश इंग्लैंड से शर्मनाक तरीके से 137 रन से हार गया। न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे और रचिन रवींद्र इन-फॉर्म बल्लेबाज हैं। मिचेल सैंटनर ने पांच विकेट झटके और ऐसा करने वाले वह टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज बन गए। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने वनडे में 41 बार एक-दूसरे का सामना किया है, जिसमें ब्लैक कैप्स ने 30 और बांग्लादेश ने 10 जीते हैं। एक का कोई नतीजा नहीं निकला।

आत्मविश्वास से ओतप्रोत न्यूजीलैंड टीम को विश्व कप में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिये चेपॉक की धीमी पिच पर बांग्लादेश के खिलाफ शुक्रवार के मैच में स्पिनरों से सावधान रहना होगा । न्यूजीलैंड (प्लस 1 . 958), भारत (प्लस 1.5)और पाकिस्तान (प्लस 0.92) के चार चार अंक है लेकिन रनरेट के मामले में कीवी टीम आगे है। इस मैच को जीतने पर उनकी स्थिति और मजबूत हो जायेगी। नियमित कप्तान केन विलियमसन और तेज गेंदबाज टिम साउदी के आने से न्यूजीलैंड का आक्रमण और मजबूत हुआ है। दोनों इंग्लैंड और नीदरलैंड के खिलाफ नहीं खेल सके थे और विलियमसन की जगह टॉम लाथम ने कप्तानी की थी। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि विलियमसन अब एसीएल चोट से उबर चुके हैं और साउदी भी अंगूठे की सर्जरी के बाद अब फिट हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

## सेंसेक्स 65 अंक टूटा निफ्टी 19,800 के नीचे

**नईदिल्ली।** आईटी शेयरों में गिरावट के कारण हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार में जारी दो दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। दोनों फ्रंटलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ग्लोबल मार्केट में आज मजबूत रूझान देखे गए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 65 अंक टूट गया। वहीं, निफ्टी में भी 17 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमशः 0.3 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ तेजी जारी रही। घरेलू शेयर बाजारों ने बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। मगर आईटी शेयरों में गिरावट के बाद बाजार ने शुरुआती तेजी खो दी। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 64.66 अंक यानी 0.10 फीसदी की हल्की गिरावट के साथ 66,408.39 अंक पर बंद हुआ।

## अदाणी को पछाड़ मुकेश अंबानी बने नंबर 1 अमीर

**नईदिल्ली।** फोर्ब्स इंडिया ने भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। ग्लोबल मीडिया कंपनी फोर्ब्स की तरफ से जारी इस लिस्ट में भारत के अरबपति उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फिर से टॉप पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। फोर्ब्स इंडिया ने 2023 के अरबपतियों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि 92 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। मुकेश अंबानी की कमाई में इस तरह की बढ़ोतरी के कई मायने हैं। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक डायवर्सीफाइड ग्रुप में बदल दिया और 92 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया।

## बैगजोन ने विस्तार के लिए फर्स्ट ब्रिज से 90 लाख अमेरिकी डॉलर जुटाए

**नईदिल्ली।** बैगज़ोन लाइफस्टाइल्स ने फर्स्ट ब्रिज इंडिया ग्रोथ फंड से 90 लाख अमेरिकी डॉलर (75 करोड़ रुपये) जुटाने की घोषणा की है। लावी की मूल कंपनी ने कहा कि वह अपनी ऑफलाइन उपस्थिति का विस्तार करने के लिए 1.50 लाख वर्ग फुट की विनिर्माण सुविधा स्थापित करने और 300 विशेष ब्रांड आउटलेट खोलने की योजना बना रही है। कंपनी की ओर से बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, विस्तार से 1,000 नौकरियों का सृजन होगा और कंपनी टियर-2 व टियर-3 शहरों के बाजारों में प्रवेश करेगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी आयुष तैनवाला ने कहा, उनके (फर्स्ट ब्रिज) पास कई सफल उपभोक्ता व्यवसायों के निर्माण का काफी अनुभव है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में हम 10 गुना बढ़ेंगे और एक बहु-श्रेणी, बहु-ब्रांड व्यवसाय बन पाएंगे।

## स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को नेट जीरो टार्गेट के लिए 47 लाख करोड़ का निवेश चाहिए

**नईदिल्ली।** घरेलू इस्पात और सीमेंट उद्योग को शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए 47 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। भारत दुनिया में इस्पात और सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दोनों ही उत्सर्जन-गहन उद्योग हैं जिन्हें कम करना मुश्किल है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मौजूदा इस्पात और सीमेंट संयंत्रों को शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में 47 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि इन दोनों क्षेत्रों को शुद्ध-शून्य का लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरिक्त परिचालन व्यय में हर साल एक लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

# एशियाड विजेताओं को क्या मिले ?

**संजय दुबे**

एशियाड के ट्रेक पर 5000 मीटर के दौड़ के अंतिम 50 मीटर में अपनी सारी शक्ति लगाकर जब दौड़ लगाई तो उनके सामने स्वर्ण पदक के जीत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एशियाड में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी को डीएसपी बनाने का लक्ष्य भी दिख रहा था। सोचिए कि एक खिलाड़ी कितनी उम्मीद का सफर तय कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि खेल जीवन बमुश्किल 12-14 साल का रहता है, उसके बाद खिलाड़ी भी दाल रोटी के चक्कर में पड़ जाता है। इसी कारण देश में खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब की कहावत घर घर में सुनाया जाता है। सचिन तेंडुलकर के मेट्रिक पास न होने का उदाहरण बच्चे दे तो 140 करोड़ में एक सचिन निकलता है जैसे कड़वे प्रवचन सुनने को मिलता है। इसका हल क्या है जिससे परिवार खुद आगे बढ़ कर अपने बच्चो को खिलाड़ी बनाने के लिए प्रेरित हो?

एक सुखद अहसास रहा चीन एशियाड खेलो में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल जीते। महिलाओ ने अपने दमखम से पुरुषों को खेल के मैदान में भी पीछे कर ये सिद्ध कर दिया कि यदि उन्हें उनका परिवार साथ दे तो वे भी देश का नाम रोशन कर सकती है।

पदक जीतने वाले विशेष कर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को केंद्र और उनके राज्य सरकार के साथ साथ अन्य राज्यो और निजी संस्थानों द्वारा नगद राशि के साथ साथ सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। 28 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों चाहे वे व्यक्तिगत रूप से जीते हो या टीम के सदस्य के रूप में, उन्हें राज्य सरकार क्लास 2 रेंक के पद पर नियुक्ति देने की व्यवस्था रखी है।

इस प्रावधान में एक लोचा है जिसे केंद्र

और राज्य सरकार के मुखिया को ध्यान में रख कर नए नियम बनाने की जरूरत है। आमतौर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलो में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी पढ़ाई के मामले में कमजोर होते है क्योंकि उनका ध्यान खेल में लगा रहता है। उनके लिए दो दो परीक्षा एक साथ होती है जिसके कारण वे खेल में बढ़ जाते है लेकिन पढ़ाई में पिछड़ जाते है। देश में चाहे यूपीएससी हों या राज्यो की पीएससी परीक्षा ईस या कोई अन्य तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरी, अनिवार्य योग्यता किसी भी संकाय की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना ही आवश्यक है। किसी भी खिलाड़ी को खेल कोटे में चयनित होने के लिए ये एक ऐसी बाधा है जिसके कारण खिलाड़ी या तो खेल या पढ़ाई में पिछड़ जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर खेल के बल पर रेल्वे में कार्यरत थी। उनके शानदार प्रदर्शन के चलते उनको पंजाब पुलिस में क्लास 2 पद डीएसपी बनाया गया। खेल के चलते हरमनप्रीत कौर ने विश्वास करके किसी विश्वविद्यालय से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में पता चला कि डिस्टेंस एजुकेशन वाली संस्थान जिसे राज्य सरकार ने मान्यता दी थी, बोगस निकली। हरमनप्रीत कौर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा क्यों है कि किसी खिलाड़ी के अंतराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने और देश के लिए पदक लाने के बाद भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई की अनिवार्यता आड़े आ जाती है? भारत और देश के राज्य की सरकारों को चाहिए कि पढ़ाई की अनिवार्यता को ऐसे खिलाड़ी जो ओलंपिक, एशियाड या अन्य अंतराष्ट्रीय खेलो में स्वर्ण पदक जीतते है तो उनकी शैक्षणिक योग्यता न देखी जाए और उन्हें ससम्मान सरकारी स्तर पर क्लास 2 रेंक की नौकरी दी जाए। रजत और कांस्य पदक जीतने वालो को क्लास 3 रेंक में बिना शर्त नौकरी दी जाए। देश के स्वाभिमान के लिए सालो मेहनत करने कर पदक जीतने वालो के लिए ये सुविधा मिलनी चाहिए। जब ऐसी व्यवस्था हो जायेगी तो किसी बच्चे के अभिभावक अपने बच्चे को खिलाड़ी बनाने के लिए जोखिम भी उठाएंगे। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब की लोकोक्ति से निजात पाने के लिए खिलाड़ियों को पढ़ाई की अनिवार्यता से मुक्त करना ही होगा।

# राजेश मूणत ने ली 3 वार्डो में मैराथन बैठकें

**रायपुर।** भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमर कस ली है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर चर्चा भी हो रही है। गुरुवार को मूणत ने 3 वार्डो में मैराथन बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। गुरुवार को राजेश मूणत क्रमश (1) दानवीर भामाशाह वार्ड, गुढ़ियारी (2) बाल गंगाधर तिलक वार्ड, गुढ़ियारी (3) रामकृष्ण परमहंस वार्ड, कोटा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष संवाद करके उनके विचार जानकर पूरे उत्साह के साथ चुनाव प्रचार में लग जाने के निर्देश दिए। मूणत ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि भाजपा संगठन की विचाधारा ,राष्ट्र के प्रति समर्पणभाव और एकजुटता हम सबकी ताक़त है,अगर आप खुद को जनता के प्रति जवाबदेह समझकर उनके साथ सपर्क स्थापित करेंगे,तो जनता भी आपकी बातों को सुनने में रूचि दिखाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि जनता इस बात से भली भांति परिचित है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही जनहित और राष्ट्रनिर्माण से जुडी सकारात्मक राजनीति करती है,जबकि कांग्रेस समेत अन्य दल अंग्रेजो की भांति फुट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं। रायपुर पश्चिम समेत सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता विकासपथ पर चलने वाली शुध्द और सकारात्मक सरकार चाहती है। हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न, केंद्र सरकार के कार्यों और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कामों को लेकर जनता के बीच जाना है। मूणत ने तीनो वार्डों में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के मध्य कार्य का बंटवारा करते हुए कहा कि अब समय कम बचा है, मतदान की तारीख तक हर सेकेंड भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुट जाएं। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस सरकार से मुक्ति दिलाकर एक बार फिर कमल खिलाएं

## चुनाव के दौरान सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करें : डॉ भूरे

**रायपुर।** कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज विधानसभा निर्वाचन के परिपेक्ष्य में विभिन्न आबकारी केन्द्रों का निरीक्षण किया, जिसमें देशी मदिरा भंडागार गुढ़ियारी तथा विदशी मदिरा गोदाम शामिल थे। कलेक्टर डॉ भुरे ने गोदाम में जाकर मदिरा के भंडारण स्थिति सुरक्षा आदि का निरीक्षण किया, साथ ही सीसीटीव्ही कैमरों और उनकी बैकअप क्षमता की जानकारी ली। उन्होंने दोनो गोदाम के प्रभारियों को कहा कि पूरे निर्वाचन के दौरान सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें, किसी भी प्रकार की गडबड़ी न होने पाए और रिकार्ड पंजी को हमेशा अद्यतन रखें। यह ध्यान रखें कि राजनैतिक दलों के प्रत्याशी से जुड़े कोई भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश न करें न किसी प्रकार की हस्तक्षेप करें। गडबड़ी पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ भुरे ने सिलतरा स्थित सर्वेश्वरी बॉटलिंग एंड बेवरेस प्राईवेट लिमिटेड और कॉन्टीनेन्टल डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड में बाटलिंग यूनिट, भराई व्यवस्था का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि पंजी अद्यतन संधारित करते रहें, सीसीटीव्ही कैमरें 24 घंटे सुचारू रूप से संचालित हो एवं इंटरनेट व्यवस्था बने रहे और विद्युत बाधित होने की स्थिति में कैमरें चालू रखने का इंतजाम करें। साथ ही हमेशा जीपीएस युक्त वाहनों में ही आपूर्ति करें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, आबकारी विभाग की उपायुक्त श्रीमती मंजूश्री कसेर, एसडीएम श्री प्रकाश टंडन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री जीपी प्रजापति सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

# दंतेवाड़ा में ओजस्वी मंडावी को मनाने में जुटी भाजपा

- बंगले में चली हाईलेवल मीटिंग, फोन पर ओम माथुर ने की बात, नहीं मानीं ओजस्वी- सूत्र

**दंतेवाड़ा।** दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से क्षुब्ध के दिवंगत नेता भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी पार्टी से नाराज चल रहीं हैं। उनके समर्थक उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर, अब ओजस्वी को मनाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता भी जुट गए हैं।

गुरुवार शाम ओजस्वी के दंतेवाड़ा निवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। जिसमें पार्टी के जिला संगठन प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी पहुंचे। जिले के 5 मंडल अध्यक्ष और कुछ नेता भी शामिल हुए थे। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और डॉ रमन सिंह ने ओजस्वी से फोन पर बातचीत की, लेकिन वो नहीं मानीं।

### निर्दलीय चुनाव लड़ाने की चल रही तैयारी

ओजस्वी के समर्थक उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने इसका खुलासा किया था। अब सूत्र बता रहे हैं कि, अगर पार्टी ओजस्वी को टिकट दे देती है तो ठीक वरना कई नेता संगठन से इस्तीफा देंगे। हालांकि, निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर ओजस्वी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

### चैतराम के घर भी मीटिंग

इधर, बीजेपी प्रत्याशी चैतराम अटामी के आवास पर भी मीटिंग हुई है। बीजेपी संगठन के कुछ नेता और समाज के लोग इस बैठक में पहुंचे हैं। ओजस्वी को मनाने और चैतराम के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

# प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम

**रायपुर।** विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाता जागरूकता हेतु सामान्य स्वीप गतिविधियों के आयोजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर स्वीप कार्ययोजना अंतर्गत मतदाता जागरूकता से संबंधित स्वीप गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में उल्लेखित है कि स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु तत्काल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर एक स्वीप

नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ-साथ समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नवप्रवेशित नये छात्र-छात्राओं को मतदान प्रक्रिया से जोडने हेतु प्रेरक कार्यक्रम चलाया जाये जिसमें कैम्पस एम्बेसडर एवं प्रोफेसर नोडल अधिकारी (स्वीप) का विशेष सहयोग लिया जाए।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में मतदाता जागरूकता के संदेशों का प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्तर पर संचालित अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। मतदाता जागरूकता से संबंधित प्रेरक नारों को शासकीय कार्यालयों की दीवारों पर खाली स्थानों में सुंदर लिखावट में प्रदर्शित किया जाए। मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/ स्टेट आईकन के संदेशों का रिकार्डेड मेसेज (ऑडियो-विडियो) का प्रसारण स्थानीय सिनेमाघरों, स्थानीय केबल टीवी, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाए। साथ ही ग्रामीण इलाकों एवं हाट बाजारों में कोटवार के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सूचनाएं यथा मतदान तिथि, मतदान समयावधि तथा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का मुनादी के माध्यम से प्रचार कराया जाये।निर्वाचन से संबंधित प्रमुख तिथियों एवं मतदान करने हेतु प्रेरक संदेशयुक्त पोस्टर डिजाइन तैयार कर सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के अधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर को प्रदर्शित किया जाए।

## 12495 लाइसेंसी हथियारों में से जमा किए गए 8807

**रायपुर।** राज्य में आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लाइसेंस शस्त्र को रखने पर पाबंदी की गई है। 12495 लाइसेंसी हथियारों में 8807 जमा किये गये हैं। 3 जब्त किये गये हैं और 10 कैंसल किये गये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 1229 प्रकरण बनाये गये हैं और इसके अंतर्गत 1284 हथियार जब्त किये गये हैं। 54 लोगों को जिलाबदर किया गया है। एमवी एक्ट के अंतर्गत 3 लाख 64 हजार 86 प्रकरणों में 18 करोड़ 49 लाख 4 हजार 157 रुपए की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अंतर्गत 1 लाख 34 हजार 206 प्रकरणों मे 1 लाख 81 हजार 527 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है तथा 1 लाख 5 हजार 863 बाउंड ओवर किये गये हैं। आबकारी मामलों में 19 हजार 891 केस दर्ज किये गये हैं इसमें 1 लाख 29 हजार 48 लीटर की 5 करोड़ 28 लाख 85 हजार 758 रुपए की शराब जब्त की गई है।

# प्रधानमंत्री मोदी राहत को रेवड़ी कहते हैं: पवन खेड़ा

- कांग्रेस का पोस्टर ' कमल का बटन दबाओगे तो निकलेगा अडानी

**रायपुर।** विधानसभा चुनाव से पहले राजीव भवन में कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा हुआ है कि कमल दबाएंगे तो अडानी निकलेगा! ये पोस्टर एआईसीसी कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राहत को रेवड़ी कहते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों को राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी अडानी को राहत देते हैं।

कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने धान खरीदी को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी

तो धान खरीदी नहीं होगी, भाजपा की प्राथमिकता में तो अडानी हैं। वे धान खरीदी जैसे कामों पर क्यों ध्यान देंगे।

ईडी की लगातार छापेमारी के पर पवन खेड़ा ने कहा कि ईडी छत्तीसगढ़ में मकान बनवाने की कोशिश में है। किसान, आदिवासी, गरीब, मध्यम वर्ग सबका स्थान हमारे दिल में है। लेकिन भाजपा सिर्फ अडानी का सोचती है। संविदा कर्मचारियों को स्थाई नौकरी देने के मुद्दे पर पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ लोगों को नियमित किया गया है और कुछ का 27 प्रतिशत वेतन भी बढ़ाया गया है।

खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता को जोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन भाजपा धर्म का कार्ड खेलकर आपको और हमको तोड़ना चाहती है। यह गरीब का भला नहीं करना चाहते।जहां संवाद से काम चलता हो, वहां यह विवाद खड़ा करते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक अच्छी और नई सरकार देने का संकल्प लेते हैं। क्योंकि पंजा दबाएंगे तो हर वर्ग को राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

## इस चुनाव में भाजपा जनता से माफीनामा जारी करें : बैज

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा जनता से माफीनामा जारी करें। भाजपा को इस बात का प्रायश्चित करना चाहिये जनता ने उन्हें तीन बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था उस घोषणा पत्र के वायदो को पूरा करने के लिये तीन बार सरकार चलाने का अवसर दिया था लेकिन भाजपा वायदा करके वो मुकर गयी। 2003 के घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हर

आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने का, युवाओं को 500 रू. बेरोजगारी भत्ता देने का, 2008 में वायदा किया किसानों को धान का 300 रू. बोनस देने का, 2013 में वायदा किया था धान की कीमत 2100 रू. देंगे और 300 रू. बोनस कुल 2400 रू. प्रति क्विंटल धान खरीदी करने का कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। एक बार फिर से जनता को ठगने के लिये घोषणा पत्र बनाने जनता के बीच जाने की बात कर रहे है। अब जनता उनके घोषणा पत्र में क्यों भरोसा करेगी? हमने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया हमारे 36 में से 34 वायदें पूरा हुये। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक मुख्यमंत्री अपने वायदा को पूरा कर रहे है। छत्तीसगढ़ में सरकार में रहते 15 साल वादाखिलाफी करने वाले भाजपाई किस नैतिकता से नये वादो की बात कर रहे है।

## छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 20 विधायकों का कट सकता है टिकट

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर गुरुवार शाम से दिल्ली में ष्टश्वष्ट की बैठक जारी है। चर्चा है कि इस बार पार्टी अपने 20 से 24 विधायकों का टिकट काट सकती है। साथ ही पार्टी को पिछले चुनाव में जिन 22 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, वहां भी नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं।हालांकि इसके बाद 5 सीटों पर हुए उप चुनाव में कांग्रेस ने 3 पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में उसके पास 71 सीटें हो गईं। इस लिहाज से देखें तो 19 सीटें अभी कांग्रेस के खाते में नहीं हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस का लिस्ट में 40 नए चेहरे होंगे।दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में हो रही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण को लेकर मंथन का दौर जारी है। बैठक में प्रदेश प्रभारी सैलजा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की पहली सूची 15 अक्टूबर को जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे लेकर उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि, पितृ पक्ष तक तो सूची जारी नहीं की जाएगी, इतना तय है। आज ष्टश्वष्ट की बैठक होनी है। इस बैठक में पहले और दूसरे चरण के नामों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि जिन विधायकों के टिकट काटे जाने की चर्चा है उनमें रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा का भी नाम है। आज की बैठक बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। प्रदेश स्तर की बैठकों के बाद सभी 90 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक और स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकों के बाद ये नाम तय किए गए हैं।

## केंद्र सरकार बतायें इन नेताओं ने कब सुरक्षा मांगी थीः शुक्ला

**रायपुर।** केंद्र सरकार ने राज्य के चुनावों को प्रभावित करने के लिये 24 भाजपा नेताओं को सुरक्षा दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को बदनाम करने के लिये भाजपाइयों को सुरक्षा दिया है। सुरक्षा के लिये सिर्फ भाजपा का सदस्य होने को पैमाना माना गया है। क्या दूसरे दलों के नेताओं को खतरा नहीं है जो सिर्फ भाजपा के नेताओं को

सुरक्षा दी गयी है? कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी गयी है? भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ की छवि खराब करने के लिये अपने नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा दिया है। भाजपा बतायें कि जिन 24 भाजपा नेताओं को सुरक्षा दी गयी, पिछले पांच सालों में उन्होंने कितनी बार अपनी सुरक्षा के लिये राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन से आवेदन किया था। केंद्र सरकार यह भी बतायें कि इन सुरक्षा प्राप्त 24 नेताओं ने कब केंद्र सरकार से सुरक्षा के लिये आवेदन किया था जो केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाया। कांग्रेस चुनौती देती है कि भाजपा के इन नेताओं के सुरक्षा मांग का आवेदन सार्वजनिक करें।छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। वह काल्पनिक मुद्दे गढ़ कर जनता में भ्रम फैलाती है। भाजपा के सारे बड़े नेता पिछले पांच सालों से सुरक्षा लेकर घूम रहे है।

## अब चुनावी स्लोगन छत्तीसगढ़ी में खोज रहेः वर्मा

**रायपुर।** प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और समूची भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी नारा तक तैयार करने की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के नारे है तैयार हम को चुरा कर अरुण साव अपनी राजनीति चमकाने में लगे है। छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे भाजपाई अब तो कार्यक्रम, यात्रा और नारा भी कांग्रेस से चुराने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास

छत्तीसगढ़ की जनता के लिए झूठ और जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके जुमलों की हकीकत भी उजागर हो चुकी है। 15 साल रमन सिंह को अवसर था कि वह छत्तीसगढ़ के पुरखों के द्वारा देखे गए सपनों को साकार कर सकें, छत्तीसगढ़ी प्रथा-परंपरा, रीति-रिवाज, खान-पान, छत्तीसगढ़िया संस्कृति और स्वाभिमान की उपेक्षा करने वाले भाजपाई अब चुनाव नजदीक आते हैं छत्तीसगढ़ी स्लोगन खोजने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह को लगातार 15 साल अवसर दिया था, की स्थानीय तीज त्यौहार हरेली, तीजा पोरा, गोवर्धन पूजा, विश्व आदिवासी दिवस जैसे छत्तीसगढ़ी परंपरा के सहभागी बने, आयोजन करें, स्थानीय कलाकारों को ऐसे आयोजनों में अवसर दें, माता कौशल्या और राम वन गमन पथ का काज करें, माता गुड़ी, देवगुड़ी और लीला मंडलियों का संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन कर सके लेकिन सत्ता में रहने के दौरान उन्हें कमीशनखोरी के आलावा और कुछ याद ही नहीं आया।

## सरकार के कारनामे देखकर वाकई दुनिया चकित हैः शर्मा

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल तक घपले घोटाले कमीशनबाजी भ्रष्टाचार माफिया राज चलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। वह

बघेल सरकार के पापों पर पर्दा डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह सिरे नहीं चढ़ने वाली। उन्हें भ्रम हो गया है कि वह छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल के गुणगान सुना जाएंगे और यहां की जनता उनकी बातें सुन लेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो भी नेता आता है, वह भूपेश बघेल की शान में तरह-तरह के अफसाने सुना कर चला जाता है। चाहे राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुनखड़गे हों, प्रियंका गांधी हों या खेड़ा जैसे कांग्रेस के कोई भी नेता हों, यह सभी भूपेश बघेल का यश गान करने के लिए विवश हैं बल्कि अभिशप्त हैं। क्योंकि भूपेश बघेल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसी के पैसों से कांग्रेस देश भर में चुनाव लड़ रही है

# पेट्रोल-डीजल का वितरण अधिकारियों की अनुमति से होगा

**रायपुर।** विधानसभा निर्वाचन-2023 को ध्यान में रखते हुए डीजल और पेट्रोल का रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले के हर पेट्रोल पंप संचालक को जारी कर दिए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रविधानों के तहत जारी किए गए हैं।

जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों में चार हजार लीटर डीजल और दो हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टाक के रूप में रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपो

में दो हजार लीटर डीजल और एक हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टाक के रूप में भंडारित रखना ही होगा।

### निर्देश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध होगी कार्रवाई

इस रिजर्व स्टाक का वितरण अपर कलेक्टर, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी।

### 70 सीटों पर दूसरे चरण में 17 को होगा मतदान

छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में सात नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा।

चुनाव परिणामों की घोषणा तीन दिसंबर को होगी। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की आठ विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 13 आरक्षित व सात अनारक्षित सीटें हैं। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इनमें बस्तर संभाग की जगदलपुर सीट के अलावा सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं डोंगरगढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

# हटाए गए 1.47 लाख रुपये के बैनर-पोस्टर

**रायपुर।** आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही निर्वाचन कार्यालय ने प्रदेशभर में कार्रवाई शुरू कर दी है। दो दिन के भीतर बड़ी संख्या में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वाल राइटिंग और बैनर-पोस्टर हटाया जा चुका है।

अलग-अलग जिलों में जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों से 10 अक्टूबर तक की स्थिति में कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियों जब्त किया गया। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है।

राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने को कहा गया है। संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं।

कार्रवाई के अंतर्गत बालोद, रायपुर व दुर्ग में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। बालोद में 13,578, रायपुर में 12,038 और दुर्ग में 11,039 प्रकरण दर्ज किए गए। सबसे कम मनेंद्रगढ़-चिरमिरी भरतपुर में 373, कोरिया में 615 और नारायणपुर में 634 मामले दर्ज किए गए। अन्य जिलों में प्रकरण- सुकमा 1,478, गरियाबंद 5,200 बेमेतरा 2,913, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 1,223, बालोद 13,578, जशपुर 2,461,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 373, सरगुजा में 9,881, बलौदाबाजार-भाटापारा 7,977, रायगढ़ 6,052, सूरजपुर 2,172, कांकेर 2016, बिलासपुर 4,305, दंतेवाड़ा 491, महासमुंद 6,336, जांजगीर-चांपा 4,634, बस्तर 488, कोरबा 9,106, कोंडागांव 9,262, कबीरधाम 1,468, बीजापुर 642, सारंगढ़-बिलाईगढ़ 1,401, राजनांदगांव 1350, बलरामपुर-रामानुजगंज 7,432, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2,384 कोरिया 615, नारायणपुर 634, मुंगेली 7,789, सक्ती 5,245, धमतरी 5,464 और रायपुर 12,038 संपत्तियों से वाल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.